दैनिक जागरण
संतुलन साधना भी एक कला है

दुकानदार का नाम

जैसे आसार थे, वैसा ही हुआ, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के मार्ग की दुकानों पर उनके मालिक का नाम लिखने के निर्देश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश पर रोक लगा दी और चूंकि ऐसे ही निर्देश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किए थे और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी जारी किए जाने की चर्चा हो रही थी, इसलिए उसने तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए। दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम लिखने संबंधी निर्देश इसलिए प्रश्नों के घेरे में था, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से कांवड़ मार्ग के दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखने का निर्देश जारी करते हुए यह कहा गया था कि ऐसा भ्रम को दूर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि आखिर किस तरह का भ्रम? मुजफ्फरनगर प्रशासन का उद्देश्य कुछ भी हो, उसके निर्देश से यह संदेश निकला कि कांवड़ियों को परोक्ष रूप से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि उन्हें मुस्लिम नाम वाली दुकानों से खाने-पीने की सामग्री न खरीदने का विकल्प दिया जा रहा है। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को केवल यह बताना होगा कि वे किस तरह का भोजन परोस रहे हैं, इसलिए कांवड़ियों और अन्य लोगों को अपनी पसंद का भोजन खरीदने-खाने की सुविधा और स्वतंत्रता होगी। वास्तव में यही होना चाहिए।

हर किसी को अपनी पसंद का भोजन खरीदने का अधिकार है और लोगों को यह पता होना ही चाहिए कि वे किस तरह की आहार सामग्री खरीद रहे हैं? कांवड़ यात्री ही नहीं, अन्य अनेक लोग भी शाकाहार पसंद करते हैं और कई बार वे उस दुकान से भी शाकाहार लेने से बचते हैं, जहां मांसाहार भी बनता-बिकता है। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांवड़ यात्रियों और अन्य को यह चयन करने में आसानी होगी कि वे अपनी पसंद का भोजन कहां से खरीदें और कहां से नहीं? फिलहाल यह कहना कठिन है कि आगे इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कई धार्मिक यात्राओं में हर समुदाय के लोग अपनी दुकानें लगाते हैं। इनमें खाने-पीने की दुकानें भी होती हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों को किस्म-किस्म की सुविधाएं प्रदान करने वाले भी होते हैं। उनके सामने यह बाध्यता नहीं होती कि वे अपना नाम लिखें। यह एक तथ्य है कि अमरनाथ यात्रा में खाने-पीने की सामग्री बेचने वालों के अलावा खच्चर-टेंट वाले भी मुस्लिम होते हैं। इस मामले की आगे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपेक्षा है कि वह यह देखे कि हलाल प्रमाणन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह कितना सही है?

रिश्ते भूलते लोग

मनुष्य का जीवन रिश्तों से जुड़ा है। रिश्तों के कारण ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने, सफलता पाने एवं कार्य करने की इच्छा रखता है। यदि रिश्ते मधुर हों तो जीवन सुखमय एवं खुशहाल बन जाता है, किंतु रिश्तों में खटास आते ही व्यक्ति भी टूट जाता है। भागदौड़ और अभावों से घिरी जिंदगी के चलते खून के रिश्तों की बुनियाद कमजोर पड़ना चिंता का विषय है। रिश्तों की डोर इतनी नाजुक हो चली है कि अपनों के खून से भी हाथ रंगने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां मामूली विवाद में अपनों की हत्या कर दी गई। पिछले सप्ताह मंडी जिले के बल्ह उपमंडल में भूमि विवाद में भाई को पटककर मार डालने की घटना सामने आई। शनिवार को बिलासपुर जिले में भूमि विवाद में लोहे की राड से हमला कर भतीजे ने चाची की जान ले ली। मुश्किल के समय सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं लेकिन यहां पड़ोसी भी मामूली विवाद में ऐसे कदम उठा रहे हैं, जिसके परिणाम सुखद नहीं हो सकते। नादौन में एक व्यक्ति ने पड़ोसी के विरुद्ध पुलिस में हथियार होने व गोली चलाने की आशंका जताते हुए दबिश डलवा दी। जांच में हथियार तो नहीं मिला लेकिन पीड़ित ने लोकलज्जा के कारण आत्महत्या कर ली। विवाद बांस के झुंड को लेकर था, जिस पर दोनों परिवार अपना दावा जताते हैं। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल की संस्कृति से भी ऐसी घटनाएं मेल नहीं खाती हैं। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि रिश्ते आखिर क्यों बिगड़ रहे हैं? ऐसी घटनाओं के मूल में कहीं न कहीं संस्कारों की भी बात आती है। बच्चों को जैसे संस्कार देंगे, वे वैसे ही बनेंगे। एकल परिवारों का बढ़ता चलन भी इसका प्रमुख कारण है क्योंकि व्यक्ति की सोच अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह जाती है। आवश्यक है कि सामाजिक मूल्यों व संस्कारों के साथ रिश्तों का महत्व समझा जाए। विवादों का हल संवाद से संभव है। ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए, जिनके परिणाम सुखद नहीं हो सकते हैं।

सीमाओं पर गंभीर संकट

दिव्य कुमार सोती

वर्तमान में जम्मू से लेकर मणिपुर तक जो घट रहा है, वह एक बड़ी साजिश का परिणाम है

पिछले कुछ समय से जम्मू संभाग में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए जाने वाले हमलों की संख्या में खासी तेजी आई है। इन हमलों में स्थानीय तत्वों द्वारा आतंकियों को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें प्रश्रय देने के मामले सामने आते रहने के बावजूद हम जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित कट्टर इस्लामिक तत्वों की मौजूदगी को स्वीकारने से बचते रहते हैं जो आज भी समाज, प्रशासन और मुख्यधारा की राजनीति में मौजूद हैं। यही कारण है कि यह इलाका जिस इस्लामिक कट्टरपंथ के मूल रोग से ग्रस्त है, उसका कभी उपचार नहीं हो पाया। इसकी कीमत हमें अपने जवानों और आम नागरिकों के खून से आए दिन चुकानी पड़ती है। अगर किसी को कोई संदेह हो तो जम्मू-कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन का हालिया बयान बहुत कुछ कहता है। स्वैन ने कहा कि पाकिस्तान यहां समाज के हर हिस्से में वैचारिक घुसपैठ करने में सफल रहा है। आतंकियों के घर जाना और उनसे सहानुभूति जताना मुख्यधारा के नेताओं के लिए भी सामान्य बात है। स्वैन सरकारी पद पर रहते हुए जितना बोल सकते थे, बोल गए। समझने वाले समझ सकते हैं कि उनका संकेत किनकी ओर था।

वर्तमान में जम्मू से मणिपुर तक जो घट रहा है, उसका व्यापक भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण आवश्यक है। 2020 से ही चीन के साथ भारत का सैन्य तनाव कायम है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भड़का तनाव पूर्वोत्तर तक पसर गया है। अपेक्षाकृत शांत रहने वाले उत्तराखंड एवं हिमाचल के मध्यवर्ती क्षेत्र में भी तनाव के चिह्न दिखने लगे हैं, क्योंकि भारत ने चीनी सीमा पर बढ़ती सैन्य हलचल के चलते यहां भी सैन्य तैनाती बढ़ाई है और सैन्य कमांड ढांचे में भी अहम बदलाव किए हैं।

नियंत्रण रेखा पर 2021 से संघर्ष विराम है, लेकिन पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ जारी है। इसके चलते ही जम्मू संभाग में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में तैनात रहीं सेना की अनुभवी आतंक निरोधक टुकड़ियों को लद्दाख भेजने से स्थिति और गंभीर हुई है। जम्मू से लगते पंजाब में भी खालिस्तानी तत्व फिर से सक्रिय हुए हैं। जम्मू में बढ़ते हमलों के बीच तमाम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समाप्त करने की बात कह रहे हैं, मगर बदली हुई परिस्थितियों में सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होगा दो मोर्चों पर सीधी सैन्य झड़पों की ओर कदम बढ़ाना। हालांकि, चीन को लेकर भारत सरकार ने हाल में नीति बदली है, जिसमें दलाई लामा और ताइवान के साथ भारतीय नेतृत्व द्वारा निकटता का प्रदर्शन और चीन के साथ द्वीपसमूहों को लेकर विवाद में उलझे फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती जैसे कदम शामिल हैं। वर्ष 2020 में चीन के साथ सैन्य झड़पों के बाद से ही जम्मू क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों का दौर शुरू हुआ और पाकिस्तान ने अपने सैन्य दस्तों में सक्रिय रहे लोगों को भी इस क्षेत्र में भेजा। ऐसे में इस घटनाक्रम को चीन-पाकिस्तान सहयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें चीन पाकिस्तान के जरिये सुनिश्चित कर रहा है कि लद्दाख में उसकी सेना का सामना कर रहीं भारतीय सेनाएं निश्चिंत न रह पाएं। आवश्यकता पड़ने पर जम्मू में किए जा रहे इन छोटे हमलों को पुलवामा जैसी किसी बड़ी घटना में भी बदला जा सकता है, ताकि भारत दो मोर्चों पर उलझ जाए। ऐसे में आवश्यक है कि जम्मू संभाग से आतंकियों और उनके मददगारों का जल्द सफाया किया जाए।

अवधेश राजपूत

पूर्वी सीमा पर भी भारत के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। म्यांमार में सैनिक सरकार देश के सीमावर्ती प्रदेशों में सशस्त्र विद्रोह कर रही कबीलाई शक्तियों के सामने पस्त पड़ती दिख रही है। अमेरिका और चीन इसमें अपना-अपना हित साधने में लगे हैं। एक ओर अमेरिका चिन, रखाइन और भारत के मिजोरम और मणिपुर के ईसाई हो चुके कुकी-चिन आदिवासियों को एकजुट एक ईसाई राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है, वहीं चीन म्यांमार की केंद्रीय सत्ता को कमजोर होता देख उत्तर में शान और कचिन में पूर्ववर्ती बर्मा कम्युनिस्ट पार्टी के विखंडन से उपजे सशस्त्र उग्रवादी संगठनों जैसे यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी और म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी के जरिये इन प्रांतों में अपना प्रभाव क्षेत्र बना रहा है। चीन समर्थित इन उग्रवादी संगठनों के पास हजारों गुरिल्ला लड़ाके और चीन द्वारा मुहैया कराए गए उन्नत हथियार हैं। ये उग्रवादी गुट एक तरह से चीन के अनधिकृत सशस्त्र बलों की तरह काम करते हैं। इनके माध्यम से चीन दशकों तक पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकियों को हथियार और प्रशिक्षण मुहैया कराता आया है। म्यांमार की सीमा पर कुकी-चिन ईसाई उग्रवादियों का कब्जा होने से भारत का म्यांमार के केंद्रीय इलाकों से संपर्क कट रहा है। इसके चलते भारत-म्यांमार के सहयोग से चल रही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई परियोजनाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं, वहीं मणिपुर में भी शांति स्थापित नहीं हो पा रही है।

समस्या यह है कि स्वतंत्रता के बाद से नई दिल्ली द्वारा मणिपुर के मैतेयी हिंदू समुदाय के साथ सौतेले व्यवहार और नेहरू सरकार द्वारा उनके लिए पवित्र काबो घाटी बर्मा को दिए जाने के चलते भारत के विरुद्ध गुस्सा पनपा, जिसका लाभ चीन समर्थित वामपंथी तत्वों ने उठाया। अधिकांश चरमपंथी मैतेयी गुट माओवाद से ही प्रेरित हैं। अगर भारत-म्यांमार के बीच के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों को नियंत्रण में ले चुके कुकी-चिन उग्रवादी संगठनों पर नरमी दिखाई जाती है तो जहां चीन इसका लाभ उठाकर मैतेयी माओवादी उग्रवादियों को मजबूत करेगा, वहीं म्यांमार सरकार से हमारे संबंध बिगड़ेंगे। मणिपुर और मिजोरम में ईसाई अलगाववाद भी पनपेगा। अगर म्यांमार सरकार देश पर अपना नियंत्रण बहाल नहीं कर पाती तो भारत म्यांमार में अपना सामरिक प्रभाव खोएगा। ऐसे में भारत के पास म्यांमार को लेकर भी आसान विकल्प नहीं हैं। हालांकि मणिपुर में शुरुआत सख्त राष्ट्रपति शासन से की जा सकती है, जिसमें दोनों ही समुदायों के हिंसक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि चीन के साथ सीधे टकराव या म्यांमार के विखंडन की स्थिति में अस्थिर मणिपुर बेहद गंभीर समस्या बन सकता है।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

पूरी हो शिक्षा पर समुचित खर्च की मांग

गिरीश्वर मिश्र

शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की बात तो होती है, परंतु यह तीन प्रतिशत भी नहीं हो पाता

सुधार की मांग करती शिक्षा व्यवस्था। फाइल

शिक्षा की बहुआयामी भूमिका से शायद ही किसी को असहमति हो। समाज के अस्तित्व, संरक्षण और संवर्धन के लिए शिक्षा जैसा कोई सुनियोजित उपाय नहीं है। इसीलिए हर देश में शिक्षा में निवेश वहां की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अवयव रहा है। आज ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विश्व में अग्रणी राष्ट्र अपनी शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वे शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध करने के लिए निरंतर सक्रिय हैं। देश, काल और परिस्थिति की बनती-बिगड़ती मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के कलेवर में बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक तथ्य है कि भारत में शिक्षा अनेक विसंगतियों से जूझती आ रही है। इस सबके चलते हमारी समग्र व्यवस्था चरमरा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ढलान के लक्षण लाभकारी नहीं हैं। इसका सभी स्तरों पर कुछ न कुछ नुकसान उठाना ही पड़ता है।

एक समय देश में साहित्य, आयुर्वेद, ज्योतिष, नाट्यशास्त्र, व्याकरण, योग, न्याय, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और वेद आदि अनेक विषयों का अध्ययन-अध्यापन हो रहा था। उपलब्ध ग्रंथों से इन विषयों को लेकर हुई कठिन साधना का कोई भी सहज ही अनुमान लगा सकता है। आज यह ज्ञान परंपरा सांस ले रही है। विदेशी आक्रांताओं ने हमारी देशज शिक्षा में षड्यंत्रकारी दखल दिया। इसका सबसे दूरगामी असर अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ। यह बात प्रमाणित है कि भारत का दोहन और शोषण ही साम्राज्यवादी अंग्रेजी राज का एकल उद्देश्य था। पाश्चात्य ज्ञान को रोप कर यहां की ज्ञान परंपरा को विस्थापित करने का काम अंग्रेजों ने किया। भारतीय मानस को पश्चिमी सांचे में ढालना और देशज ज्ञान के प्रति भारतीयों के मन में वितृष्णा का भाव पैदा करना अंग्रेजों का उद्देश्य बन गया। परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा के समग्र, समावेशी और स्वायत्त स्वरूप विकसित करने की बात धरी की धरी ही रह गई। हम उसके अंशों में थोड़ा बहुत हेरफेर कर काम चलाते रहे।

स्वतंत्र भारत में अपनाई गई शिक्षा की नीतियां, योजनाएं और उनका कार्यान्वयन प्रायः पुरानी लीक पर ही अग्रसर हुआ। स्वतंत्र होने के बाद भी पश्चिमी माडल के जाल से आज भी हम उबर नहीं पाए हैं। शिक्षा का बाजारीकरण देशज शिक्षा को पीछे धकेल रहा और हम सब अचेत तो नहीं, पर दिग्भ्रम में जरूर पड़े रहे। लगभग दो सदी तक कायम रही अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव में हमारी सभ्यता में भी वेश-भूषा, खानपान और मनोरंजन आदि में परिवर्तन आया। इससे सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन शुरू हुआ। पाश्चात्य दृष्टि को मानक, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक मान कर उसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आरोपित किया जाता रहा। व्यवस्था की जड़ता इतनी रही कि शिक्षा के प्रसंग में उठने वाले सभी सरोकार जैसे देश का विकास, शिक्षण की गुणवत्ता, विभिन्न सामाजिक वर्गों का समावेशन, शिक्षा जगत में स्वायत्तता की स्थापना, शैक्षिक नवाचार बातचीत के विषय तो बनते रहे, किंतु वास्तविकता में यथास्थिति ही बनी रही।

आज प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक इतने पैमाने देश में चल रहे हैं और लोकतंत्र के नाम पर इतने तरह की विकृतियां पनप गई हैं कि उनसे पार पाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा में तदर्थवाद का बोलबाला बढ़ गया है। शिक्षा व्यवस्था में भारी विषमताएं आ गई हैं। सरकारी, अर्ध-सरकारी और स्ववित्तपोषित संस्थाओं की अजीबोगरीब खिचड़ी पक रही है। सबके मानक और गुणवत्ता के स्तर भिन्न हैं। फीस, प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा के तौर-तरीके भी बेमेल हैं। बच्चे को पढ़ाना अभिभावकों के लिए बरसों-बरस चलने वाला संघर्ष बन गया है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लुभावना लगता है, पर इस संकल्प को साकार करने के लिए किसी जादुई छड़ी से काम न चलेगा। उसके लिए योग्य, प्रशिक्षित और निपुण मानव संसाधन की जरूरत अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए शिक्षा में प्रवेश चाहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बजट में शिक्षा के लिए प्रविधान बढ़ाने की जरूरत है।

अनेक वर्षों से शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की बात कही जा रही है, परंतु वास्तविक व्यय तीन प्रतिशत भी बमुश्किल हो पाता है। कड़वा सच यह भी है कि खानापूर्ति से आगे बढ़ कर कुछ करने का अवसर सिकुड़ता रहा है। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए वित्त की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। फरवरी-मार्च 2024 में प्रकाशित आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि शिक्षा के लिए आवंटित राशि में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह राशि शिक्षा के लिए अपेक्षित निवेश सीमा से कम है। एक तरफ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट को कम किया गया है तो दूसरी तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अधिक राशि आवंटित की गई है। सरकार को उच्च शिक्षा में बेहतर और समावेशी अवसर पैदा करने के लिए नए क्षेत्रों में संभावनाओं को तलाशना होगा। सरकार को यह भी संज्ञान में लेना होगा कि यदि शिक्षा रूपी लोकवस्तु पर राज्य अपना निवेश नहीं बढ़ाएगा तो इसका लाभ बाजार की ताकतें उठाएंगी। इसका दोहरा नुकसान होगा। पहला, शिक्षा के लिए आम आदमी का निवेश बढ़ जाएगा। दूसरा, भारत में समावेशन की गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। विचारणीय है कि आधुनिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के प्रसार और विस्तार के लिए भी प्राथमिकता से निवेश करना होगा। सरकार द्वारा संस्थानों से स्ववित्त पोषण की उम्मीद करना शिक्षा के लोक स्वरूप को क्षति पहुंचाएगा। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा को प्रभावी बनाना ही होगा। शिक्षा को प्राथमिकता में रखना समय की मांग है।

(लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सद्कर्मों की संपत्ति

जब मनुष्य इस संसार में कदम रखता है तो वह कुछ भी लेकर नहीं आता। इसी प्रकार जब वह इस संसार को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकलता है तो उस समय भी उसके पास कुछ नहीं होता। उसके हाथ खाली होते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के मध्य जो यात्रा चलती है उस दौरान उसे अनेकों प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। कई गुणों का धारक बनने के साथ ही कुछ अवगुण भी उस पर हावी हो जाते हैं। सकारात्मक प्रवृत्तियां मार्गदर्शन करती हैं तो अवगुण मार्ग से विचलित करते हैं।

मनुष्य जीवन में संपत्ति के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है। उसकी आसक्ति अपने पूर्वजों की संपत्ति एवं स्वयं अर्जित संपत्ति में निहित होती है। वह इसे ऐसे सीने से चिपकाकर रखता है जैसे यह सब उसके पास सदैव रहने वाला है। वह यह नहीं समझता जिसे वह अपना समझ कर अभिमान में डूबा हुआ है वह उसका है ही नहीं। उसे असल संपत्ति का भान हो ही नहीं पाता। भौतिक तत्व संपत्ति नहीं हैं, बल्कि एक मरीचिका हैं। हम इनके फेर में ही उलझे रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली संपत्ति हमारे कर्म हैं, जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहेंगे। जो इस लोक और परलोक दोनों ही जगह हमारे साथ कदमताल करते नजर आएंगे।

हमें अपने कर्मों को सद्कर्म बनाना पड़ेगा। यही हमारी संपत्ति है। हमें मानवता, दया, परोपकार, दान और सहिष्णुता जैसे दिव्य दैवीय गुणों को आत्मसात करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अध्यात्म और हमारा धर्म भी हमारी संपत्ति है। इन संपत्तियों का संरक्षण भी हमें करना ही पड़ेगा। यही संपत्तियां आने वाली पीढ़ी को सौंपने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। अकूत धन संपदा को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपने के विचार से पहले उन्हें संस्कार एवं विनयशीलता की संपत्ति सौंपने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

ललित शौर्य

बाल विवाह कुप्रथा पर सख्ती जरूरी

सुनीता मिश्रा

असम सरकार की सख्त कानूनी कार्रवाई के कारण राज्य में बाल विवाह के मामलों में 81 प्रतिशत की कमी आई है

असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम, 1935 को रद करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत विशेष परिस्थितियों में कानूनी उम्र से कम उम्र में (21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 से छोटी लड़की) विवाह की अनुमति है। यह विधेयक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। तब तक मुस्लिमों के निकाह एवं तलाक का पंजीकरण 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। इसके लिए 30 दिन पहले नोटिस देना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

ध्यान दें कि असम सरकार की सख्त कानूनी कार्रवाई के कारण राज्य में बाल विवाह के मामलों में 81 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य के 30 प्रतिशत गांवों में बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है, जबकि 40 प्रतिशत गांवों में इसमें उल्लेखनीय कमी देखने को मिली जहां कभी बड़े पैमाने पर बाल विवाह का चलन था। असम सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से बाल विवाह कुप्रथा को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। पिछले वर्ष फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान एक महीने के भीतर 3,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 4,300 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उद्देश्य बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करना, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना है। इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है।

बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। बाल विवाह बच्चों के बचपन को खत्म कर देता है। इसकी वजह से लड़कियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में ब्याही गई लड़कियों का मानसिक एवं भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है। बाल विवाह होने से लड़कियां कम उम्र में मां बन जाती हैं। छोटी उम्र में मां बनने के कारण गर्भ में उनके बच्चों का भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। इससे कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं या फिर गर्भ में ही किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बाल विवाह कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह लोगों को गरीबी की ओर धकेलता है। ऐसे में असम सरकार का बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का माडल सभी राज्यों में लागू होना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

विकसित भारत का आधार बने बजट

'विकसित भारत की राह दिखाए बजट' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में तरुण गुप्त ने बजट से जुड़ी अपेक्षाओं को रेखांकित किया। उन्होंने उचित ही लिखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही पुलिस एवं न्यायपालिका के लिए व्यापक संसाधनों को आवंटित करने की आवश्यकता है। शिक्षा के बिना किसी भी समाज का उत्थान संभव नहीं और यदि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न हों तो न केवल देश की उत्पादकता प्रभावित होती है, बल्कि लोगों की बचत एवं जमा पूंजी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए राज्य को इन दोनों ही मोर्चों पर ध्यान देकर सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि इन आवश्यक सेवाओं के लिए लोग मजबूरी में निजी क्षेत्र पर आश्रित हैं। हालांकि निजी क्षेत्र का उभार पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, लेकिन यदि सार्वजनिक सेवाएं सहजता से उपलब्ध होंगी तो उससे एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सक्षमता का भाव भी बढ़ेगा। याद रहे कि शांति समृद्धि की पहली सीढ़ी है। इसलिए यदि देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना होगा तो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनानी होगी। इस दिशा में पुलिस सुधार अत्यंत आवश्यक हो चले हैं। जिन राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अच्छी है वहां निवेश भी अधिक है और औद्योगिक गतिविधियों से लेकर रोजगार की तस्वीर कहीं बेहतर है। ऐसे में अन्य राज्यों को भी इससे सीख लेते हुए कानून एवं व्यवस्था के ढांचे को दुरुस्त करना चाहिए। सरकारी एजेंसियों के साथ ही नागरिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। विशेषकर स्वच्छता के मामले में सब कुछ राज्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यदि इस स्तर पर नागरिक भी सामुदायिक प्रयासों को गति दें तो देश की स्थिति सुधरेगी। आयकरदाताओं को भी बजट में कुछ राहत मिले तो उपभोग पर उसका सकारात्मक असर पड़ सकता है और इस मोर्चे पर राजस्व की क्षति अन्य मोर्चों पर उपभोग से संभावित कर संग्रह से पूर्ति हो सकती है। इससे विकसित भारत की संभावनाएं और बलवती होंगी।

प्रिया पांडेय, नोएडा

आसान नहीं चीन से आयात रोकना

उम्मीद है कि इस बार के आम बजट में चीन को आर्थिक झटका देने के लिए कोई न कोई फैसला लिया जाएगा। भारत में जब से चीनी सामान आना शुरू हुआ है, तब से न जाने भारत के कितने ही छोटे-मोटे उद्योग धंधे या तो बंद हो गए हैं या उनपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक भी कि थी। अर्थात कुछ चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाया था। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार हमारा देश चीन से लगभग 8,000 से अधिक वस्तुओं का आयात करता है। और यह भी सच है कि चीन से आने वाले कई ऐसी वस्तुएं हैं, जिनकी मैन्यूफैक्चरिंग भारत में आसानी से की जा सकती है, लेकिन उद्यमियों की तरफ से सार्थक कोशिश नहीं की गई। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में स्वदेशी और कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश की सरकार चीन से आर्थिक लड़ाई खुलकर नहीं लड़ सकती और चीनी सामान पर पूर्ण प्रतिबंध आसानी से लगा सकती, क्योंकि विदेशी व्यापार, आयात-निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ समझौते हुए होते हैं, जिनकी उल्लंघना करना हमारे देश के लिए भारी पड़ सकती है। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि 'डब्ल्यूटीओ नियमों के कारण अब किसी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या सैन्य समस्याएं क्यों न हों।' चीन से आर्थिक लड़ाई लड़ने में हमारे देश के नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए नागरिकों को चीनी सामान पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। अगर हमारे देश के लोग अनावश्यक चीनी सामान का प्रयोग करना भी छोड़ दें तो भी चीन को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। इनमें मुख्यतः बच्चों के खिलौने और इलेक्ट्रानिक सामान आदि हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

कांवड़ और न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने पक्ष-विपक्ष में तर्क सुनने के बाद उस विवादास्पद आदेश पर शुक्रवार तक रोक लगा दी है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों व कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने साफ कर दिया है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिक, कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस भी दिया है। तय है, याचिकाकर्ता ने अपनी मजबूत दलीलों से सर्वोच्च न्यायालय से अपने अनुकूल अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया है और अब गेंद इन सरकारों के पाले में है, उन्हें अपने आदेश के बचाव में अकाट्य तर्क के साथ पेश होना पड़ेगा। दुकानों-ठेलों पर मालिक को नाम लिखने के लिए बाध्य करने वाला यह आदेश व्यापक है और इससे समाज में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अतः संविधान की रोशनी में आगे बढ़ना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि न्यायालय अपने अंतरिम आदेश में भी सतर्क है। न्यायालय की भी यही मर्जी है कि कांवड़ियों (तीर्थयात्रियों) को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप शाकाहारी भोजन परोसा जाए और स्वच्छता के मानकों को बनाए रखा जाए। न्यायालय को प्रथम दृष्टया भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की चिंता है और याचिकाकर्ता भी इस मोर्चे पर अपनी आशंकाओं का समाधान चाहते हैं। एक तर्क यह भी है कि केवल नाम या पते के प्रदर्शन से शुचिता या पवित्रता बहाल नहीं होगी और न इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति होगी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया है कि आप किसी रेस्तरां में व्यंजन सूची के आधार पर जाते हैं, न कि कौन परोस रहा है। यदि किसी दुकानदार का नाम-मजहब स्पष्ट हो जाएगा, तो पहचान के आधार पर बहिष्कार की आशंका है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अनेक शाकाहारी रेस्तरां के मालिक हिंदू हैं, पर वहां मुस्लिम भी काम करते हैं, तो क्या इस आधार पर भी भेदभाव किया जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि इस आदेश के खिलाफ आशंकाओं की एक लंबी फेहरिस्त तैयार हो गई है। एक दिलचस्प विवरण तो न्यायमूर्ति भट्टी ने सुनाया, 'केरल में एक शाकाहारी होटल है, जिसे एक हिंदू चलाता है और एक होटल मुसलमान चलाता है। एक न्यायाधीश के रूप में मैं उस होटल में जाता था, जिसे मुसलमान चलाता था और वह स्वच्छता का अंतरराष्ट्रीय मानक बनाए रखता था।' मतलब, शुचिता और गुणवत्ता का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, खान-पान सेवा में सही मानसिकता होनी चाहिए।

> कांवड़ मार्ग पर लागू किए गए आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है और वह उचित ही इस आदेश के निहितार्थ में जाना चाहता है।

बहरहाल, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। सावन का पहला सोमवार बीत चुका है और अब दुकानदारों के साथ ही कांवड़ियों पर भी किसी तरह का दबाव नहीं है, पर दुकानदारों के साथ ही कांवड़ियों और अन्य ग्राहकों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। गुणवत्ता और स्वच्छता के प्रति सजगता जरूरी है, यह एक ऐसा मसला है, जिसके लिए केवल सरकारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अगर लोग यह तय कर लें कि वहीं खाएंगे और वहीं से सामान लेंगे, जहां विश्वस्तरीय मानक बनाए रखा जाता है, तो आधी से ज्यादा समस्या का समाधान यहीं हो जाएगा। यहां ज्यादा जिम्मेदारी खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग की है, पुलिस की नहीं। अंतिम फैसले में न्यायालय को जिम्मेदारी का भी स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए, ताकि आशंकाओं की कोई गुंजाइश न बचे।

लोकसेवा आयोग पर बना रहे विश्वास

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

संघ लोक सेवा आयोग व प्रदेश आयोगों के सदस्यों ने दशकों तक बेहतरीन काम किया, पर बीते कुछ वर्षों में उनके विरुद्ध जो आरोप लगे हैं, उनसे आम जन का विश्वास डगमगा गया है।

आजादी के फौरन बाद जब बहुत सारे औपनिवेशिक अवशेषों को नष्ट करने की मांग उठ रही थी, एक ब्रिटिश निर्मिति को समाप्त करने से तत्कालीन गृह मंत्री और लौहपुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि देश की एकता के लिए इस स्टील फ्रेम की जरूरत है। यह स्टील फ्रेम आईसीएस (इंडियन सिविल सर्विस) और आईपी (इम्पीरियल पुलिस) नामक दो अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मौजूद था। आजाद भारत में उन्हें नए अवतारों आईएएस (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) और आईपीएस (इंडियन पुलिस सर्विस) के रूप में सुरक्षित रखा गया। नई बोतल में पुरानी शराब की तरह इन सेवाओं का अहंता, परीक्षा, सेवा शर्तों से संबंधित ढांचा कमोबेश बरकरार रहा।

संविधान लागू होने के बाद एक बड़ा फर्क यह जरूर आया कि संघ और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के रूप में ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं बन गईं, जो अभ्यर्थियों का एक निश्चित पद्धति से आकलन करती हैं और फिर वांछित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थियों की सिफारिश सरकार को भेजती हैं। यह व्यवस्था बहुत प्रभावशाली तरीके से वर्षों तक काम करती रही, पर किसी भी अन्य संस्था की तरह लोक सेवा आयोगों में भी गिरावट आई और इन दिनों कुख्यात पूजा खेडकर ने बेदर्दी से इस सड़ांध को इस कदर उजागर कर दिया है कि बदबू के मारे हमारी नाक फटी जा रही है।

प्रादेशिक और संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को सांविधानिक हैसियत हासिल होने के कारण इन्होंने दशकों तक बेहतरीन काम किया, पर बीते कुछ वर्षों में उनके विरुद्ध जो आरोप लगे हैं, उनसे आम जन का विश्वास डगमगा गया है। पिछले दिनों कई प्रदेश लोकसेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाए गए, यहां तक गिरफ्तार भी किए गए हैं। कुछ वर्ष पूर्व पंजाब लोकसेवा आयोग के सदस्यों के पास से करोड़ों रुपये बरामद किए गए थे।

इसी तरह इलाहाबाद लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष के विरुद्ध इतने संगीन आरोप लगे कि उसी शहर में स्थित उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा। ये तो सिर्फ चंद नमूने हैं।

गिरावट की सबसे बड़ी वजह शायद यह है कि इन संस्थाओं के सदस्यों के रूप में हाड़-मांस के पुतलों की नियुक्ति होती है और उनका चयन करने वाले भी उन्हीं की तरह के मनुष्य ही होते हैं। समस्या की शुरुआत होती है, जब सरकारें अवसरों या अध्यक्ष के पद पर जाति, क्षेत्र या सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां करने लगती हैं। इन अयोग्य सदस्यों से योग्य अभ्यर्थियों के चयन की अपेक्षा करना उनके साथ ज्यादती ही होगी। संविधान द्वारा स्वतंत्र इस संस्था की राजनीतिक नियुक्तियां खुद ही अपनी स्वायत्तता समर्पित करने को कितना उत्सुक रहती हैं, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मुझे एक लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक रह चुके मित्र अधिकारी ने एक बार बातचीत के दौरान बताया कि उनके अध्यक्ष परीक्षा फल घोषित करने के पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मांगते थे। वे मुख्यमंत्री से बात कर यह भी बताना नहीं भूलते थे कि उनकी जांच के कितने उम्मीदवार सफल हुए हैं। ये अध्यक्ष महोदय बड़ी लंबी कानूनी जद्दोजहद के बाद ही हटाए जा सके और उनके कार्यकाल की सीबीआई जांच वर्षों से लंबित है।

पूजा खेडकर के प्रकरण ने तो पूरे तंत्र की विफलता के नए कीर्तिमान कायम कर दिए हैं। पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत संघ लोक सेवा आयोग यह नहीं पकड़ पाया कि पूजा अपने निर्धारित अवसरों से काफी अधिक - बारह बार लिखित परीक्षा में बैठी थी। इसके लिए उसे सिर्फ अपने या माता-पिता के नामों की वर्तनी में छोटे-मोटे हेर-फेर करने पड़े, अपने निवास का पता बदलना पड़ा या अलग-अलग कोणों से खींची गई तस्वीरें फॉर्म पर चिपकानी पड़ीं। यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि बिना किसी अंदरूनी मानवीय मदद के संस्था के कंप्यूटरों को धोखा देना इतना आसान रहा होगा। वह एक ऐसी सीट पर चुनी गई थी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर-मलाईदार और शारीरिक अक्षमताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित थी। पूजा का पिता राज्य सरकार का एक रिटायर अधिकारी है। अपनी सेवा के दौरान वह अपनी संपत्ति का वार्षिक ब्योरा जमा करता होगा और निश्चित रूप से यह फर्जी रहा होगा, क्योंकि अवकाश प्राप्ति के बाद जब वह चुनाव लड़ा, तो चुनाव आयोग को दिए विवरणों के अनुसार उसके, उसकी पत्नी और खुद उसकी बेटी पूजा के नाम से करोड़ों रुपयों के मूल्य की चल-अचल संपत्तियां थीं। स्पष्ट है, वह सेवा के दौरान महाराष्ट्र सरकार को दिए गए वार्षिक विवरणों में झूठ लिखता रहा होगा, नहीं तो वहां ही आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण बन जाता और वह पकड़ा जाता। संघ लोक सेवा आयोग ने कितनी लापरवाही से पूजा द्वारा दिए गए विवरणों की जांच की, यह तो इसी से स्पष्ट है कि साल-दर-साल वह बिना पकड़े गए फर्जीवाड़ा करती रही।

यह भी कम चिंताजनक नहीं है कि पूजा खेडकर ने जिन शारीरिक अक्षमताओं का दावा किया था, उनकी पुष्टि कराए बिना उसे नियुक्ति दे दी गई। यहां भी आयोग और नियुक्ति पत्र जारी करने वाले केंद्रीय सरकार के विभाग ने पर्याप्त और जरूरी पड़ताल की परवाह नहीं की। इन विवादों की चर्चा चल ही रही थी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की खबरें मीडिया में गश्त करने लगीं। हालांकि, उनसे जुड़े सूत्रों ने समझाने की कोशिश की है कि इस्तीफे और पूजा प्रकरण में कोई संबंध नहीं है, पर क्या ही अच्छा होता, यदि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए यह कदम उठाया होता।

पाठकों ने हिंदी की कालजयी कहानी *हार की जीत* पढ़ी होगी, जिसमें नायक बाबा भारती को एक ठग द्वारा अपंग बनकर उनका घोड़ा चुराने पर अपनी क्षति से अधिक इस बात की चिंता होती है कि लोग अब किसी असहाय पर विश्वास करना छोड़ देंगे। पूजा खेडकर का प्रकरण समाने आने के बाद लोगों ने उन तमाम लोगों पर शक करना शुरू कर दिया है, जिन्हें आर्थिक या शारीरिक अक्षमताओं के कारण चयन में मदद मिली है। इनमें से अधिकांश बिना किसी छूठ के अपनी योग्यता के बल पर चुने गए होंगे, लेकिन पूजा ने सबको संदिग्ध बना दिया है। सोशल मीडिया पर चुन-चुनकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है। कोई यह नहीं सोच रहा है कि पहले ही प्रकृति की ज्यादतियों के शिकार इन लोगों पर शक कर हम उन्हें अतिरिक्त घाव दे रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बढ़ते भारत की बेहतर तस्वीर पेश कर रहा आर्थिक सर्वे

दलीप कुमार | अर्थशास्त्री

सोमवार को संसद-पटल पर रखा गया साल 2023-24 का आर्थिक सर्वे विकसित होते भारत की तस्वीर दिखा रहा है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 8.2 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि 2022-23 में यह 6.5 प्रतिशत थी। यह स्थिति तब है, जब विश्व की औसत विकास दर 3.2 प्रतिशत ही है। यही नहीं, भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 2024-25 में 6.5 से सात प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया है। अर्थव्यवस्था में यह भरोसा इसलिए बना है, क्योंकि सर्वेक्षण मानता है कि देश का भू-राजनीतिक महत्व, आर्थिक झटकों को झेलने की क्षमता और ठोस व स्थिर घरेलू वृद्धि से भारत आर्थिक रूप से लगातार मजबूत बना रहा है। यही कारण है कि अब विशेष तौर पर शोध व अनुसंधान के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है।

बहरहाल, सर्वे में सबकी नजर रोजगार के आंकड़ों पर थी। बेरोजगारी बढ़ने को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोला जाता रहा है, मगर आर्थिक सर्वे की मानें, तो देश में बेरोजगारी घटी है। 2017-18 में यह दर जहां 17.8 प्रतिशत थी, वहीं साल 2022-23 में यह घटकर 10 प्रतिशत रह गई। अच्छी बात है कि शहरी बेरोजगारी में भी कमी आई है, भले ही यह बेहद मामूली ही क्यों न हो। दरअसल, आम लोगों की नजर में रोजगार का मतलब सरकारी या स्थायी नौकरी होता है, पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर भी सरकार रोजगार की स्थिति नापती है और यह आंकड़ा बताता है कि 2019 में जहां 61.1 लाख कर्मचारियों के पास ईपीएफओ खाता था, वहीं 2024 में यह बढ़कर 131.5 लाख हो गया। यानी, पांच वर्षों में करीब-करीब दोगुनी संख्या में नए कामगार ईपीएफओ से जुड़े हैं। सुखद है कि श्रमबल में महिलाओं की संख्या भी अच्छी-खासी बढ़ी है और उनमें 2017-18 से लेकर 2022-23 में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

> यह आर्थिक सर्वे कृषि विकास दर की बेहतरी का भी संकेत दे रहा है, जिसमें औसतन चार प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।

महंगाई को लेकर भी आर्थिक सर्वे में कुछ अलग कहानी दिखती है। मुद्रास्फीति दर, जो 2022-23 में 6.7 प्रतिशत थी, वह 2023-24 में घटकर 5.4 हो गई है। इसमें मूलतः थोक महंगाई दर शामिल है, वैसे, खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है और यह पिछले साल के 6.6 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई, जिसकी ठोस वजहें भी हैं। वास्तव में, जलवायु परिवर्तन को खाद्य मुद्रास्फीति दर बढ़ने की एक बड़ी वजह माना जाता है। प्रकृति का अनुकूल न रहना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे कई कारक हैं, जो हमारी खेती को प्रभावित कर रहे हैं। इन सबसे खाद्य मुद्रास्फीति ऊपर-नीचे होती रहती है। वैसे, विशेषकर आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं। चावल, दाल आदि खाद्यान्नों में बहुत ज्यादा उछाल नहीं है।

सामाजिक सुरक्षा की बात करें, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर), यानी कॉरपोरेट जगत की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ी है। यह जिम्मेदारी उन कंपनियों पर लागू होती है, जिनकी सालाना कमाई 1,000 करोड़ या सालाना लाभ पांच करोड़ रुपये है। उनको अपने तीन साल के औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत समाज की बेहतरी के कार्यों पर खर्च करना होता है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक, इस राशि में 53 फीसदी की वृद्धि हुई है और यह 2017-18 की 17,096 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 2021-22 में 26,278 करोड़ हो गई है, जो संकेत है कि उद्योगों के लिए देश में माहौल अनुकूल है। यह भी एक वजह है कि चीनी निवेश की अनुमति दे दी गई है। माना गया है कि द्विपक्षीय रिश्तों में आई खटास के कारण सरकार ने चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, मगर आम जनता के हित में अब ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका फायदा यह भी होगा कि टैक्स की चोरी नहीं होगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।

आर्थिक सर्वे कृषि विकास दर की बेहतरी का संकेत दे रहा है, जिसमें औसतन चार प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, यह सर्वे भारत की तरक्की की गाथा है। उसके मुताबिक, कोरोना महामारी से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था तेजी से उबर रही है। लिहाजा, जीडीपी के हिसाब से विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब जल्द ही शीर्ष चार में शुमार हो सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सत्य का बोध तभी होगा

हमारा जीवन अधिकांशतः समय में व्यतीत होता है; यहां समय कालक्रम के मिनट, घंटे, दिन अथवा वर्ष के अर्थ में नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्मृति के अर्थ में है। हम समय के गणित में जीते हैं, समय के ही परिणाम में। हमारा मन अनेक विगत दिवसों का फल है और वर्तमान केवल अतीत से भविष्य की ओर जाने का मार्ग है। हमारा मन, हमारी क्रियाएं, हमारा अस्तित्व समय पर आधारित है। समय के बिना हम विचार नहीं कर सकते, क्योंकि विचार समय का ही परिणाम है; विचार अनेक बीते दिनों का परिणाम है और वह स्मृति के अभाव में संभव नहीं है। स्मृति समय है, क्योंकि समय दो प्रकार का होता है- क्रमिक और मनोवैज्ञानिक।

एक समय बीते हुए कल के रूप में घड़ी के अनुसार होता है और दूसरा, स्मृति के अनुसार। क्रमिक समय से इनकार करना बेतुकी बात होगी, तब तो आपकी गाड़ी ही छूट जाया करेगी। परंतु क्रमिक समय के अतिरिक्त क्या वस्तुतः कोई दूसरा समय होता है?... इसमें कोई शक नहीं कि समय, मनोवैज्ञानिक समय मन की उपज है। विचार की बुनियाद के बिना समय का वजूद नहीं होता। वर्तमान के संदर्भ में वह बीते हुए कल की स्मृति मात्र है। तात्पर्य यह कि बीते हुए कल के अनुभव की स्मृति वर्तमान की प्रतिक्रिया के रूप में भविष्य को निर्मित करती है और यह विचार की ही प्रक्रिया है।

विचार प्रक्रिया समय के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रगति का आभास देती है, परंतु क्या यह क्रमिक समय की तरह वास्तविक है और क्या हम उस मनोगत काल का उपयोग शाश्वत और कालातीत को समझने के साधन के रूप में कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, प्रसन्नता बीते हुए कल की नहीं होती, सदा वर्तमान में होती है। वह एक समयातीत अवस्था होती है। मुझे नहीं मालूम कि आपने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं कि जब आप गहन उल्लास की अवस्था में होते हैं, तो एक सर्जनात्मक आनंद की अवस्था में होते हैं। उस क्षण में काल नहीं होता, वहां केवल प्रत्यक्ष वर्तमान होता है।

> जब हम गहन उल्लास की अवस्था में होते हैं, तब एक सर्जनात्मक आनंद की स्थिति में होते हैं। उस क्षण में काल नहीं होता, वहां केवल प्रत्यक्ष वर्तमान होता है।

वर्तमान के इस अनुभव के बाद मन का प्रवेश होता है। वह स्मरण करता है और आनंद की उस अवस्था को अधिकाधिक संचित करने बनाए रखना चाहता है। इस प्रकार वह काल का सृजन करता है। अतः काल, समय 'और अधिक' द्वारा सर्जित किया जाता है; समय संचय-वृत्ति भी है और निरासक्ति भी और यह निरासक्ति मन की संचय-वृत्ति से अलग नहीं है। इसलिए, मन को सिर्फ समय में अनुशासित करना कालातीत को जानने के लिए नाकाफी है।... मन जब निश्चल है, शांत है, कोई समाधान नहीं तलाश रहा; जब वह न तो प्रतिरोध कर रहा और न ही उपेक्षा, तभी वह सत्य का प्रत्यक्ष बोध कर पाता है।

जे कृष्णमूर्ति

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 23 जुलाई, 1949

किसानों को राहत

देश की जनता का अधिकतर भाग किसानों और मजदूरों से बना है। उनकी खुशहाली पर ही देश की खुशहाली निर्भर करती है। विदेशी राज में उनकी घोर उपेक्षा की गई। उनका खूब शोषण हुआ। उनको गरीबी, अज्ञान और रोग के गर्त में धकेल दिया गया। कांग्रेस ने, जबकि वह विदेशी राज्य को हटाने के लिए लड़ रही थी, किसानों और मजदूरों को यह आश्वासन दिया था कि स्वराज्य होने पर उनकी दयनीय अवस्था का अन्त कर दिया जायेगा। स्वराज्य में उनका कोई शोषण नहीं करने पायेगा। उन्हें रोग और अज्ञान के पंजे से मुक्त किया जायेगा। कांग्रेस ने कहा था कि वह जिस स्वराज्य की स्थापना के लिए लड़ रही है, वह वास्तव में किसान-मजदूर राज्य होगा। कांग्रेस को अपने उन पुराने आश्वासनों और वादों को पूरा करना है। कांग्रेस ने जब से शासन की बागडोर अपने हाथों में सम्हाली है, तब से वह ऐसे कानून बनाने का प्रयास कर रही है, जिनसे किसानों को शोषण से मुक्ति मिले।

बिहार में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए एक कानून बन चुका है और उसे गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिल चुकी है। यह कानून एकदम जमींदारी प्रथा को समाप्त नहीं कर देगा। इसमें कुछ समय लग जायेगा। वह इसलिए कि कांग्रेस ने सर्वत्र जमींदारों को मुआवजा देने का सिद्धांत स्वीकार किया है। प्रांतीय सरकारों के पास इतना रुपया नहीं है कि एक ही बार में सब जमींदारों को मुआवजा दिया जा सके। इसलिए बिहार में वार्षिक आमदनी के लिहाज से जमींदारों को अनेक श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है और प्रतिवर्ष अमुक श्रेणी के जमींदारों की जमींदारियां हस्तगत कर ली जायेंगी। इस प्रकार आशा की जा सकती है कि कुछ ही वर्षों में बिहार में जमींदारी प्रथा का अन्त हो जायेगा। किसान और सरकार का सीधा सम्बन्ध कायम हो जायेगा।

बिहार की भांति युक्तप्रांत की सरकार ने भी जमींदारी प्रथा को खत्म करने का फैसला कर लिया है और इस उद्देश्य से उसने एक बिल प्रांतीय असेम्बली के सामने उपस्थित कर दिया है। युक्तप्रांत जमींदारों का गढ़ है और उनकी ओर से इस बिल का काफी विरोध हुआ है। किन्तु प्रांतीय सरकार प्रारंभिक कठिनाइयों को पार कर चुकी है और यह आशा की जा सकती है कि जमींदारी उन्मूलन कानून बिना किसी अधिक विलम्ब के स्वीकृत हो जायेगा।

तकनीक पर इतनी निर्भरता ठीक नहीं

तकनीक पर आज हम कितने निर्भर हो गए हैं, यह तो खूब नजर आता है, लेकिन बीते दिनों माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी के बाद दुनिया भर की जो हालत हुई, वह अकल्पनीय थी। हर कंपनी, खासकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामचीन कंपनी अपना एक बैकअप प्लान (विजनेस कंटिन्यूटी प्लान) हमेशा तैयार रखती है, लेकिन हमने देखा कि संकट के समय इस पर अमल नहीं हो सका। नतीजतन, खराब रिस्पॉन्स टाइम भी हमें देखने को मिला, जिससे कई देशों को खासा नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, भारत जैसे देशों में तो हजारों की संख्या में विमानों की आवाजाही थम गई। बैंकों और शेयर बाजारों पर भी इसका काफी खराब असर पड़ा। भले ही, यह एक सेफ्टी पैच के कारण हुआ, लेकिन जो हुआ, वह अकल्पनीय था। इससे न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, बल्कि अन्य तकनीकी कंपनियों की साख पर भी बट्टा लग गया।

इससे विश्व को एक सबक भी मिला कि तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता हमें कभी-कभी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है, इसलिए इतनी निर्भरता ठीक नहीं है। आशंका यह भी बढ़ गई है कि डार्क जोन के कारण पहले से ही त्रस्त दुनिया की मुसीबत कहीं ऐसी तकनीकी खराबियों से और न बढ़ जाए? साफ है, हम सबको मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि यदि तकनीक इस कदर विफल हो जाए, तो हमारा बैकअप प्लान तैयार हो, ताकि उससे प्रभावित हुए बिना हम अपना कामकाज निरंतरता के साथ करते रहें।

मुनीश कुमार, टिप्पणीकार

विकट स्थिति

माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी गड़बड़ी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोचिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिये दुनिया पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर हो जाएगी, तब क्या होगा? तब तो तकनीकी गड़बड़ी ही नहीं, सेंधमारी का खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा एक नुकसान हैकरों के वारे-न्यारे कर सकता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा, जब हजारों करोड़ रुपये का निवेश करके कोई उपग्रह छोड़ा जा रहा हो, या अस्पताल में मरीजों की जान बचाने के लिए गंभीर ऑपरेशन किए जा रहे हों और अचानक वहां की तकनीक विफल हो जाए! ऐसे में, हमें कितना बड़ा नुकसान होगा? साफ है, किसी तकनीक को पूर्णतः टूटरहित बनाकर ही बाजार में उतारना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी विकट परिस्थिति में लोगों को नुकसान न होने पाए। इसके लिए जरूरी फायरवाल इस्तेमाल करना होगा। तकनीक को एक विज्ञान ही रहने दें, उसे जीवन के ऊपर हावी न होने दें।

विभूति बुधवया, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
तकनीक पर निर्भरता

यदा-कदा ही होती ऐसी बड़ी गड़बड़ी

माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में जो तकनीकी गड़बड़ी आई, वह वाकई सबक लेने योग्य मामला है, लेकिन सिर्फ एक घटना के आधार पर यह कहना कि तकनीक पर हमारी इतनी निर्भरता ठीक नहीं, गलत होगा। जबकि, हम जानते हैं कि तकनीक ने हमारे जीवन को कितना सुगम बनाया है। 'कर लो दुनिया मुट्ठी में' भले कभी एक कंपनी की टैगलाइन हुआ करती थी, लेकिन आज वाकई यही सच्चाई है। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में इसीलिए सिमट आई है, क्योंकि हमने नई-नई तकनीक पर भरोसा किया है, उसकी अच्छाइयों को आत्मसात किया है और उसे वक्त व जरूरत के अनुकूल लगातार विकसित किया है। ऐसे में, एक घटना से हम अपने कदम पीछे नहीं खींच सकते या तकनीक की लानत-मलामत नहीं कर सकते।

यह सही है कि शुक्रवार को जो हुआ, वह ठीक नहीं था, लेकिन ऐसी घटना आखिर घटती कितनी है? तमाम विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि उन्होंने पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया था। इसका मतलब है कि यह अपनी तरह की पहली घटना थी। जाहिर है, अब जब हमें पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम अपनी तैयारी भी उसी के अनुरूप करेंगे। प्रकृति में ही काफी कुछ पहली बार होता है या यूं कहें कि पहली बार हमारा उससे सामना होता है, तो हमें दिक्कत होती ही है, लेकिन अगली बार हम उससे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। कोरोना महामारी को ही देखिए, यह हमारे जीवन काल की ऐसी पहली महामारी थी और हमने पीछे न हटते हुए उसके खिलाफ प्रभावी टीका तैयार किया। आज स्थिति यह है कि कोरोना से हमें भय नहीं लग रहा। ठीक ऐसा ही कुछ तकनीकी दुनिया में भी होता है। वहां भी कोई चीज यदि पहली बार होती है, तो उसे अगली बार के लिए नजीर के तौर पर देखा जाता है और उससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी की जाती है।

यह वैज्ञानिक युग ही नहीं, नई-नई तकनीक व प्रौद्योगिकियों के विकास का भी युग है। ऐसे में, हम अपने कदम पीछे नहीं खींच सकते। पूरी दुनिया आज नई-नई तकनीक के विकास पर जोर दे रही है और वह भी ऐसी तकनीक, जो इंसानों के लिए सुरक्षित है। यह आगे भी होता रहेगा। तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में, तकनीक पर हमारी निर्भरता दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाएगी। रही बात ऐसी घटनाओं की, तो कभी-कभार यदि तकनीक विफल भी हो जाती है, तो उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। हम उससे सबक लेकर कहीं तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।

महिमा तिवारी, टिप्पणीकार

अपने भीतर की प्रसन्नता को बनाए रखना सीखें

हम में से प्रत्येक की इच्छा प्रसन्न रहने की होती है, लेकिन हम किसी-न-किसी अज्ञात कारण से प्रभावित होकर दुखी रहते हैं। अपने भीतर की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमारी आंतरिक शांति पर बाहरी परिवेश का असर न हो

अध्यात्म

श्री श्री परमहंस योगानंद

सादा जीवन एवं उच्च विचार आपका लक्ष्य होना चाहिए। अपने भीतर प्रसन्नता की सभी अवस्थाओं को बनाए रखना सीखें। आपकी प्रसन्नता किसी भी बाह्य परिस्थिति से कदापि प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपका परिवेश कैसा भी हो, उसे अपनी आंतरिक शांति को स्पर्श न करने दें। अपना विश्लेषण करें। जैसा आपको होना चाहिए और जैसा आप बनना चाहते हैं, वैसा ही स्वयं को बनाएं। लोग सच्चा संयम कम ही सीखते हैं। वे ऐसे कार्य करते हैं, जो उनके उच्चतम कल्याण के लिए हानिकर होते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं को सुखी बना रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपको जिस कार्य को जब करना चाहिए, उसे तब करना; और जिसे आप जानते हैं कि इस कार्य को नहीं करना हानिकारक है, इससे बचना चाहिए। यही वास्तविक सफलता और प्रसन्नता की कुंजियां हैं।

अपने मन को बहुत से कार्यों में मत उलझाए रखें। विश्लेषण करें कि आपको उनसे क्या प्राप्त होता है और देखें कि क्या वास्तव में वे महत्वपूर्ण हैं। अपना समय नष्ट न करें। मैं प्रायः कहता हूं, 'यदि आप दो घंटा पढ़ते हैं, तो अपनी आध्यात्मिक दैनंदिनी में एक घंटे तक लिखें; और यदि आप दो घंटे लिखते हैं, तो तीन घंटे तक मनन करें; और यदि आप तीन घंटे तक लिखते हैं, तो सारा समय ध्यान करें।' चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपना मन अपनी आत्मा की शांति पर निरंतर लगाए रखता हूं। आपको भी अपनी चित्त रूपी सुई को सदा आध्यात्मिक आनंद रूपी उत्तरी ध्रुव की ओर लगाए रखना चाहिए। तब कोई भी आपके संतुलन को विचलित नहीं कर सकता।

याद रखें, यदि प्रतिदिन आप स्वयं को पिछले दिन से अधिक अच्छा व्यक्ति नहीं पाते, तो आप पीछे की ओर जा रहे हैं– स्वास्थ्य में, मानसिक शांति में और आत्मिक आनंद में। क्यों? क्योंकि आप अपने कार्यों पर पर्याप्त नियंत्रण का अभ्यास नहीं करते हैं। आपने स्वयं ही अपनी आदतें बनाई हैं और आप स्वयं ही उन्हें बदल सकते हैं। यदि आप गलत ढंग से सोचते रहे हैं, तो अच्छे लोगों की संगति और अध्ययन तथा ध्यान करने का निश्चय करें। संगति का परिवर्तन आप में बहुत अंतर ला सकता है। जब आप यहां आते हैं, चाहे इन कुछ घंटों के लिए ही सही, तो आपकी मानसिकता में परिवर्तन आता है, आप एक नवीन शांति का अनुभव करते हैं। जब आप किसी नृत्य अथवा भोज के लिए जाते हैं तो आपका मन प्रायः अशांत, अधीर और उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद यदि आप एक भिन्न, शांत वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो आप फिर से अधिक शांतिमय अनुभव करते हैं। आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली, जीकि आपकी इच्छाशक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है, वह है आपका परिवेश। यदि आवश्यकता हो तो उसे बदल दें। जब तक आप मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते, आप एक अच्छे वातावरण की सहायता के बिना वह कभी नहीं बन सकते, जो आप बनना चाहते हैं। जब आपको अच्छा बनने के प्रयास में कठिनाई आ रही हो, तो आध्यात्मिक संगति और अन्य प्रेरणादायक प्रभाव अति आवश्यक है।

स्वयं को और अधिक अच्छा बनाने में आत्म-विश्लेषण भी आवश्यक है। यदि आप निर्भीक होकर स्वयं का विश्लेषण कर सकें, तो आप दूसरों के द्वारा किया गया आलोचनात्मक विश्लेषण भी बिना झिझक के सहने योग्य हो जाएंगे।

संसार में पहले से ही बहुत सारी बुराइयां हैं। बुराई के विषय में बात न करें, न सोचें और न ही बुरा करें। गुलाब की भांति बनें, और आत्मिक अच्छाई की मधुर सुगंध को चारों ओर बिखेरें। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराएं कि आप उनके मित्र हैं, उनके सहायक हैं, विनाशक नहीं। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं, तो स्वयं का विश्लेषण करें और गुणों को अपने में विकसित करें। अपने

मन से यह विचार निकाल दें कि आपके स्वभाव में बुराई की कोई भूमिका है, और तब यह समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव करा दें कि आप ईश्वर का प्रतिबिंब हैं। मात्र अपने शब्दों से नहीं अपितु अपने व्यवहार से। प्रकाश पर बल दें और अंधकार समाप्त हो जाएगा। अध्ययन करें, ध्यान करें और दूसरों का भला करें।

एकांत महानता का मूल्य है। अंतर में अकेले रहें। अनेक लोगों की तरह लक्ष्यहीन जीवन व्यतीत न करें। ध्यान करें और अच्छी पुस्तकें अधिक पढ़ें। जानने के लिए अनेक प्रेरणादायक बातें हैं और फिर भी व्यक्ति अपना समय मूर्खता से बिता देता है। यदि आप एकाग्र नहीं होते और महान पुरुषों के ज्ञान का आचरण नहीं करते तो सुख कभी नहीं आएगा। आपकी सहायता के लिए धर्मग्रंथों में और अन्य सच्ची पुस्तकों में, उनके विचार उपलब्ध हैं।

इसलिए निरंतर नई उत्तेजनाओं की खोज में समय नष्ट न करें। अपने भीतर ध्यान में केंद्रित रहें। सुख ध्यान करने पर, पुस्तकों द्वारा महापुरुषों के विचार जानने पर और उत्कृष्ट एवं दयालु लोगों की संगति में रहने पर आश्रित है। एकांत का आनंद लें, परंतु जब आप दूसरों से मिलना चाहें, तो अपनी संपूर्ण मित्रता एवं प्रेम के साथ मिलें, जिससे कि वे लोग आपको कभी नहीं भूलें, बल्कि सदा याद रखें कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिले थे, जिसने उन्हें प्रेरित किया और उनका मन ईश्वर की ओर मोड़ दिया।

आस्था-अनास्था

समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद

मंगल-गुरु योग : संघर्ष के साथ सफलता भी देगा

मंगल-गुरु योग के बारह राशियों पर क्या फल होते हैं?

-रामकुमार अग्रवाल, देहरादून

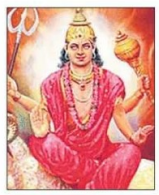

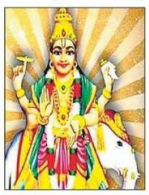

मंगल ग्रह 12 जुलाई, 2024 को शाम 06.54 पर वृष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहां यह 27 अगस्त सुबह 04.40 तक रहेंगे। वृष राशि में गुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मंगल-गुरु युति 27 अगस्त, 2024 तक रहेगी। वृष राशि में मंगल-गुरु युति का बारह राशियों पर प्रभाव:

मेष : आर्थिक लाभ। नई नौकरी। परिवार में मांगलिक कार्य। कुछ रुके काम बनेंगे।

वृष : नए संबंध-संपर्क बनेंगे। आमदनी के कुछ नए स्तोत्र की प्राप्ति। स्वास्थ्य समस्या। घर के सदस्य का स्थान परिवर्तन।

मिथुन : खर्च की अधिकता। पारिवारिक जीवन एवं साझेदारी में विवाद। निवास, पदाई या कार्यस्थल में परिवर्तन। विवाद में सफलता।

कर्क : अधिकांश कार्यों में सफलता। बड़े भाई-बहनों से लाभ। आर्थिक तरक्की। कुछ पुरानी समस्या का समाधान। परिवार में मांगलिक कार्य।

सिंह : भौतिक सुख-सामग्री, चल-अचल संपत्ति की खरीदारी। लाभकारी परिवर्तन। अधिकांश कार्यों में सफलता।

कन्या : पराक्रम बढ़ेगा। रुके कार्य बनेंगे। छोटे भाई-बहनों से संबंधित शुभ समाचार। अतिरिक्त बौद्धिक श्रम से काम बनेंगे।

तुला : संघर्षपूर्ण सफलता। स्वास्थ्य संबंधी अस्थिरता। लेनदेन एवं विवादित मामलों का निपटारा होगा।

वृश्चिक : परिवार में मांगलिक कार्य। कुछ रुके कार्य बनेंगे। नए संबंध-संपर्क बनेंगे।

धनु : तरक्की। मान-सम्मान में वृद्धि। पुरानी स्वास्थ्य समस्या का समाधान। परिवार में मांगलिक कार्य।

मकर : शुभ-अशुभ प्रभाव। आर्थिक लाभ के साथ खर्च की अधिकता। पुरानी समस्या का समाधान। जोखिमपूर्ण कार्यों से परहेज करें।

कुंभ : शनि की सादेसाती पर लगाम। घरेलू सुख-सामग्री, चल-अचल संपत्ति बढ़ेगी। तरक्की, आर्थिक लाभ। मान-सम्मान की प्राप्ति। अतिरिक्त प्रभार मिल सकता है।

मीन : भाग्य का साथ। रुके कार्य बनेंगे। मान-सम्मान मिलेगा। तरक्की, घर में मांगलिक कार्य। विदेश यात्रा, नई खरीददारी। बड़ी सफलता। भाग्य का साथ मिलेगा।

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अक्सर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें- धर्मक्षेत्रे, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)

बोधकथा

ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को खाली करना जरूरी है

एक बार व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, 'कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे ज्ञान पाना चाहता हूं, जिससे मेरा जीवन बदल सके।'

बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, 'यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो तो तुम आज से दस दिन बाद मेरे पास आना।' वह व्यक्ति दस दिन बाद फिर बुद्ध के पास आया और कहा, 'अब दस दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें।' बुद्ध का उत्तर फिर यही था, 'यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो, तो दस दिन बाद आओ।'

ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि दस दिन बाद आना। आखिरकार उस व्यक्ति का धैर्य टूट गया। इस बार उसने बुद्ध से पूछा, 'आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। ऐसा क्यों?' बुद्ध ने उससे एक गिलास पानी लाने को कहा। वह व्यक्ति पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, 'जाओ, एक गिलास पानी और ले आओ।' वह उनके निर्देशानुसार पानी से भरा एक और गिलास ले आया। अब बुद्ध ने कहा, 'पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो।' उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसा ही किया। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह गंदा हो गया। अब बुद्ध ने उससे कहा, 'पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो।' इस पर उस व्यक्ति ने कहा, 'यदि मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल बाहर गिरेगा, बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पानी से भरा हुआ है, उसमें दूसरे गिलास का पानी कैसे आ सकता है?

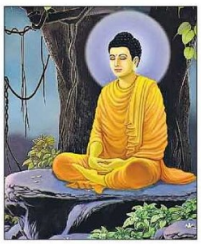

इस पर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, 'मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बुरे ज्ञान से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में कैसे समा सकता है? यदि मैं ज्ञान देने लगूंगा तो वह ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन को नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः खाली होना आवश्यक है।' भगवान बुद्ध का कथन सुनकर उस व्यक्ति को उनकी बात का मर्म समझ में आ गया।

अश्वनी कुमार

सप्ताह के व्रत-त्योहार 23 जुलाई से 29 जुलाई 2024

23 जुलाई (मंगलवार) : श्रावण कृष्ण द्वितीया तिथि प्रातः 10.24 तक। भद्रा रात्रि 08.58 मिनट से। पंचक प्रारंभ प्रातः 09.21 मिनट से। शक श्रावण प्रारंभ। मंगलागौरी व्रत प्रारंभ।

24 जुलाई (बुधवार) : श्रावण कृष्ण तृतीया प्रातः 07.31 तक। भद्रा प्रातः 07.31 मिनट तक। पंचक। श्री गणेश चतुर्थी व्रत। चतुर्थी तिथि का क्षय।

25 जुलाई (गुरुवार) : श्रावण कृष्ण पंचमी रात्रि 01.59 मिनट तक। नाग पंचमी (राजस्थान व बंगाल)। पंचक।

26 जुलाई (शुक्रवार) : श्रावण कृष्ण षष्ठी रात्रि 11.31 मिनट तक। भद्रा रात्रि 11.31 मिनट से। पंचक।

27 जुलाई (शनिवार) : श्रावण कृष्ण सप्तमी रात्रि 09.20 मिनट तक। भद्रा प्रातः 10.26 मिनट तक। गंडमूल विचार। पंचक समाप्त दोपहर 01 बजे।

28 जुलाई (रविवार) : श्रावण कृष्ण अष्टमी सायं 07.28 मिनट तक। गंडमूल प्रातः 11.48 मिनट तक।

29 जुलाई (सोमवार) : श्रावण कृष्ण नवमी सायं 05.56 मिनट तक। भद्रा रात्रि 05.21 मिनट (सूर्योदय पूर्व) से।

पं. ऋषिकांत गोस्वामी

महर्षि वरुण ने भृगु को दिया ब्रह्म ज्ञान

उपनिषदों की कथाएं

महर्षि वरुण के पुत्र भृगु के मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने पिता, वरुण के पास गए और बोले, 'भगवन! मुझे ब्रह्म विद्या की शिक्षा दीजिए, जिससे मुझे ब्रह्म-तत्त्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए।' वरुण ने अपने पुत्र की इच्छा से परिचित होकर कहा, 'अन्नमय शरीर तथा उस शरीर के भीतर प्राण, आंखें, कान, वाणी और मन इन सबको ब्रह्म ज्ञान का द्वार जानो। ब्रह्म से लेकर तृणपर्यंत सब भूत जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसकी सत्ता से जीवित रहते हैं, अंत में जिसके भीतर प्रवेश करते हैं और तदुपरांत होकर लीन हो जाते हैं, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए।'

भृगु ने जब अपने पिता से इस प्रकार की बात सुनी तो वह ब्रह्म का ध्यान करने के उद्देश्य से तप करने लगे। तप करने पर उन्हें यह बोध हुआ कि अन्न ब्रह्म है क्योंकि अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवन धारण करते हैं और फिर अन्न में ही जाकर प्रवेश करते हैं।

जब उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे फिर अपने पिता महर्षि वरुण के पास गए और बोले, 'मुझे ब्रह्म-तत्त्व की शिक्षा फिर से दीजिए।' पिता ने कहा, 'इंद्रियों की बाहरी वृत्तियों को भीतर की ओर करके तप द्वारा तत्त्व-चिंतन करो। तप से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।' भृगु ने जब यह सुना तो वह फिर तप करने लगे। तप करने से उन्होंने जाना कि प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण से ही समस्त प्राणी जन्म लेते हैं, प्राण ही के द्वारा जीवन धारण करते हैं और फिर प्राण ही में जाकर लीन हो जाते हैं। वह फिर अपने पिता वरुण के पास गए और बोले, 'मुझे ब्रह्म-विषय की शिक्षा दीजिए।' वरुण ने कहा, 'तप ही ब्रह्म को जानने का एकमात्र उपाय है, इसलिए तुम तप करते रहो।' भृगु फिर तपस्या में मग्न हो गए। तपस्या करने पर उन्हें यह बोध हुआ कि मन ही ब्रह्म है और मन से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, मन ही के द्वारा वे जीते हैं और मन ही में जाकर विलीन हो जाते हैं। भृगु फिर अपने पिता के पास गए और बोले, 'मुझे ब्रह्म-विद्या की शिक्षा दीजिए।' वरुण बोले, 'सौम्य! तपस्या द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, इसलिए तुम निरंतर तप करते जाओ।'

भृगु फिर तपस्या करने लगे। इससे उन्होंने जाना कि विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं, विज्ञान से ही वे जीवन धारण किए हुए हैं और अंत में विज्ञान में ही प्रवेश करके उसमें विलीन हो जाते हैं। इसके पश्चात वह फिर महर्षि वरुण के पास गए और बोले, 'मुझे इसके आगे ब्रह्म-विद्या की शिक्षा दीजिए।' वरुण बोले, 'तपस्या द्वारा ही तुम ब्रह्म का रहस्य जान सकते हो, इसलिए और अधिक तप करो।'

भृगु फिर तप में जुट गए। तप करते-करते उन्हें बोध हुआ कि आनंद ही ब्रह्म है, और उसी से इन सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उसी के द्वारा सब प्राणी जीवन धारण करते हैं और अंत में उसी में जाकर विलीन हो जाते हैं। वरुण द्वारा भृगु ने जो यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया वह परम अंतर-आकाश में स्थित है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है, वह परम ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह अंत में अन्न से युक्त होता है, अन्न का भोग करने में समर्थ होता है, संतान सुख प्राप्त करता है और ब्रह्म तेज द्वारा महान कीर्ति अर्जित करता है।'

इलाचंद्र जोशी

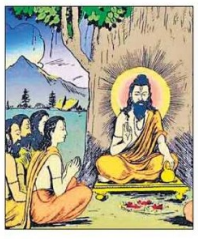

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें। बातचीत में संतुलन भी बनाए रखें। कुटुंब-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी।

वृष : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र भी बढ़ेगा।

मिथुन : संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध व वाद-विवाद से बचें। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। कठिनाई आ सकती है। सोहद का भी ध्यान रखें। सर्च बढ़ेंगे।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु संयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में सम्मान मिलेगा।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संयत रहें। अति उत्साही होने से बचें। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है।

कन्या : मन में निराशा व असंतोष रहेगा। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

तुला : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में भी लाभ के अवसर मिलेंगे। सर्च में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में व्यस्तता बढ़ सकती है। लाभ के अवसर मिलेंगे। लेखनादि कार्यों में सम्मान मिल सकता है।

धनु : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान हो सकता है, परंतु वाणी में सौम्यता हो सकती है। कारोबार का विस्तार हो सकता है और परिवार से दूर जा सकते हैं।

मकर : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है।

कुंभ : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, परंतु मन कुछ परेशान भी हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। सर्च में वृद्धि होगी। रुके धन की प्राप्ति हो सकती है।

मीन : मन अशांत हो सकता है। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। बौद्धिक कार्यों से धन की प्राप्ति हो सकती है। मान-सम्मान भी मिलेगा।

वर्ग पहेली : 7672

हिलोर मारना (4)

ऊपर से नीचे

1. उपासना करना; पूजा करना; सेवा करना (4,3)
2. अस्थिर; चलायमान; चंचल; चपल; द्रव (3)
3. पानी भरने वाला; पालकी उठाने वाला (3)
5. चौकस करना; सजग करना; होशियार करना (4,3)
7. फैलाव; प्रसार; उन्नति (3)
8. भाग्य का जोर मारना; भाग्य चमकना; माथा चमकना (3,4)
10. बाजा बजाने वाला; वादन करने वाला; वाद्य यंत्र बजाने वाला; संगीतज्ञ (3)
13. कनकना; झींगा; पतला; बारीक (3)
14. मुस्लिम पद्धति का विवाह; शादी (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली (उत्तर अगले अंक में)

बाएं से दाएं

1. धारण क्षमता; आकार; परिमाण; फैलाव (4)
3. ज्यों-का-त्यों; बिना उलट फेर का; जो व्याकुल न हो; शांत; व्यवस्थित (4)
6. रजत; निर्मल; शुभ्र; श्वेत; सफेद (3)
7. जो घना न हो; दुर्लभ; पतला (3)
9. महिला विधायक; विधान निर्मात्री संस्था; राज्यों की विधान सभा व विधान परिषद् (4)
11. भय, संकोच या लज्जा के कारण छिपना; बचना; घुड़कना; डांटना (4)
12. नामवाला; नाम से प्रसिद्ध (3)
14. जिसको कोई वासना न हो; ममताहीन; क्रूर; हृदयहीन (3)
15. पानी भरने का घाट (4)
16. उत्साहित होना; ध्वजारोहण करना; फहराना;

वर्ग पहेली 7671 का उत्तर

सुडोकू : 7656

*आसान

1	5	9		7	6			3
			1					
		7			3			4
3	8			5		2		
		4				5		
		5		2			7	1
8			6			4		
					8			
5			2	3		1	8	9

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

हल : सुडोकू नं.7655

6	4	5	1	7	8	3	2	9
3	8	7	9	2	5	1	6	4
1	2	9	4	6	3	7	8	5
5	3	4	8	1	7	6	9	2
9	1	8	6	3	2	5	4	7
2	7	6	5	9	4	8	1	3
8	5	1	7	4	9	2	3	6
7	9	3	2	8	6	4	5	1
4	6	2	3	5	1	9	7	8

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

23 जुलाई, मंगलवार, 01 श्रावण (सौर) शक संवत् 1946, 08 श्रावण मास प्रविष्टे (पंजाब पंचांग) 2081, 16 मुहर्रम सन् 1446, श्रावण कृष्ण द्वितीया तिथि (विक्रमी संवत्) प्रातः 10.24 तक। सौभाग्य योग, गर करण। चंद्रमा मकर राशि में प्रातः 09.21 मिनट तक उपरांत कुंभ राशि में।

सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 08.58 मिनट से। पंचक प्रारंभ प्रातः 09.21 मिनट से। शक श्रावण प्रारंभ। मंगलागौरी व्रत प्रारंभ।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

क्या वास्तु शास्त्र के अनुसार एक लाइन में तीन दरवाजे नहीं होने चाहिए। इसका क्या परिणाम होता?

-राधेश्याम चतुर्वेदी, मथुरा

एक लाइन में तीन दरवाजे नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से एनर्जी रुक नहीं पाती है तथा कमाने के बाद भी बरकत नहीं होती। पैसा आने के साथ ही जाने के रास्ते भी बन जाते हैं। इसके लिए आप निम्न उपाय करें–

- बीच वाले दरवाजे पर एक विंड चाइम लगा दें। आखिरी वाले दरवाजे पर पर्दा लगा दें। सबसे पहले दरवाजे पर तीन क्रिस्टल बॉल इस प्रकार लगाएं कि दो कॉर्नर में तथा एक बीच में लगाएं। यथासंभव कोई एक दरवाजा बंद रखें।

कल्पमेधा

उस साहस को जानने का अभ्यास करो, जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जीवन के सत्य को बताने की हिम्मत है। समस्त विश्व में उसका कोई हनन नहीं कर सकता।

– विवेकानंद

विकास का अर्थ

आर्थिक समीक्षा से बजट की रूपरेखा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें पिछले वर्ष की आर्थिक स्थितियों का लेखाजोखा पेश किया जाता है। इसी आधार पर आगामी वर्ष के लिए नीतियां निर्धारित होती हैं। इस वर्ष चूंकि आम चुनाव थे, पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया गया था। आज इस वर्ष के लिए आम बजट पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछला वर्ष आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण रहा। कोरोना काल के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी की दर निरंतर घट रही है। भारत की कुल श्रमशक्ति में से सत्तावन फीसद स्वरोजगार में लगी हुई है। महंगाई के मोर्चे पर जरूर थोड़ी चुनौती उभरती रही है, पर अंतरराष्ट्रीय स्थितियों से तुलना करें तो इस पर अपेक्षाकृत काबू पाया जा सका है। इस वर्ष मानसून अच्छा रहने की वजह से जल्दी ही महंगाई की लक्षित दर हासिल कर ली जाएगी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा। इस वर्ष विकास दर के साढ़े छह से सात फीसद रहने का अनुमान है। 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख रोजगार सृजित करने की जरूरत रेखांकित की गई है। हालांकि वैश्विक मंदी की वजह से निर्यात के क्षेत्र में चुनौतियां बनी रह सकती हैं।

पिछले वर्ष के आर्थिक रुझानों के आधार पर सरकार ने इस वर्ष निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। यों पहले से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक बजटीय प्रावधान और योजनाएं लागू की जाती रही हैं। निजी उद्योगों की सुविधा के लिए कर, कर्ज आदि में छूट के अलावा श्रम कानूनों को लचीला बनाया गया। इससे पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ा है। पिछले वर्ष निजी क्षेत्र के निवेश में नौ फीसद की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वित्तमंत्री ने कहा है कि अब निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने का वक्त है। अगले वित्तवर्ष में बजट घाटा घट कर साढ़े चार फीसद तक रह जाने की संभावना जताई गई है। नए बजट में कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से हवाई सेवा क्षेत्र को बढ़ाने, शिक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बिठाने, ड्रोन निर्माण में तेजी लाने और राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जाहिर है, आम बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं पर बल होगा।

हालांकि इस सर्वेक्षण को विपक्ष ने अतिरंजित और आंकड़ों का खेल बताया तथा बजट में व्यावहारिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। दरअसल, आंकड़ों में अर्थव्यवस्था की बुलंदी और व्यावहारिक धरातल पर बेहतरी के बीच कोई सहसंबंध नजर नहीं आता। एक तरफ तो आंकड़ों में तेजी से तरक्की करती अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर नजर आती है, मगर आम जनजीवन के स्तर पर बेहतरी के कोई संकेत नजर नहीं आते। बेशक सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने का दम भरती है, पर हकीकत यह है कि लोग रोजमर्रा उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और क्रयशक्ति घटने की वजह से परेशान हैं। रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को भरोसे का कोई काम मिलना कठिन बना हुआ है। जिस निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है, वह उस अनुपात में नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा। इसलिए बजट में अगर गंभीरता से व्यावहारिक नीतियों पर विचार नहीं होगा, तो मुश्किलें आसान नहीं होंगी।

खेती और खुदकुशी

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, मगर यहां के किसान आज भी कई तरह की समस्याओं और परेशानियों से घिरे हुए हैं। यही वजह है कि किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की एक रपट के मुताबिक, इस वर्ष जनवरी से जून के बीच राज्य में 1,267 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,290 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें 5,207 किसान और 6,083 खेतिहर मजदूर थे और इनमें महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा थे। इसी तरह वर्ष 2021 में कृषि कार्यों में लगे 10,881 लोगों और 2020 में 10,677 लोगों ने अपनी जान दे दी। किसानों की खुदकुशी के पीछे पारिवारिक कर्ज या आर्थिक संकट को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। हालांकि इन आर्थिक परेशानियों के भी कई स्तर हैं। मसलन, प्राकृतिक आपदा, कर्ज का बोझ, फसलों की बढ़ती लागत, घटती आय और फसलों के उत्पादन में गिरावट। महाराष्ट्र सरकार की रपट में कहा गया है कि राज्य में पिछले छह माह में किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले विदर्भ क्षेत्र के अमरावती मंडल में सामने आए हैं।

बहुत से किसान खेती के लिए बैंक और साहूकारों से कर्ज लेते हैं और अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल बर्बाद हो जाए या उत्पादन कम हो, तो उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। उर्वरक, खेती के लिए उपकरण और सिंचाई पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है, जबकि किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लिहाजा, किसानों की आर्थिक परेशानियां बढ़नी स्वाभाविक हैं। लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग भी लंबित है। दूसरी ओर, उद्योग जगत के ऋणों के प्रति सरकार के नजरिए में जो नरमी देखी जाती है, वह किसानों के लिए नहीं दिखती। ऐसे में किसानों की समस्याओं की जटिलता अगर उन्हें आत्महत्या के कगार पर ले जाती है तो इसे एक नतीजे के तौर पर देखा जा सकता है। इस समस्या के निराकरण के लिए ठोस और कारगर उपाय किए जाने जरूरत है, अन्यथा यह स्थिति और जटिल होगी।

बांग्लादेश के साथ भारत की चुनौतियां

बदलती वैश्विक स्थितियों को भांपते हुए बांग्लादेश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रही हैं, इसके पीछे उनका 'विजन 2041' है।

ब्रह्मदीप अलूने

बांग्लादेश अगले वर्ष चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। शेख हसीना सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह भी दिलचस्प है कि 1971 में बांग्लादेश की एक स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता को रोकने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया था। मगर बदलती वैश्विक स्थितियों को भांपते हुए बांग्लादेश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रही हैं, इसके पीछे उनका 'विजन 2041' है।

बांग्लादेश भारत की 'एक्ट ईस्ट पालिसी' का अभिन्न अंग और बड़ा व्यापारिक साझीदार है। भारतीय प्रधानमंत्री और शेख हसीना ने 9 मार्च, 2021 को पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था। इस सेतु को उस सिलीगुड़ी गलियारे का विकल्प माना गया, जो भारत की अखंडता की रक्षा के लिए बेहद खास माना जाता है। चीन और बांग्लादेश के बीच ऐसे कई मैत्री सेतु पहले से प्रभाव में हैं। चीन ने बांग्लादेश में एक मैत्री पुल का इस प्रकार निर्माण किया है, जिसमें स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस्लामी और चीनी विशेषताओं से सुसज्जित किया है। बांग्लादेश में चीन का निवेश बढ़कर लगभग डेढ़ अरब अमेरिकी डालर हो गया है। लगभग सात सौ चीनी कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बांग्लादेश चीन की 'वन बेल्ट वन परियोजना' का प्रमुख साझीदार बन गया है और इसे 'विजन 2041' और 'स्मार्ट बांग्लादेश' के सपने के साकार होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है।

बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध मजबूत बनाने के लिए चीन ने वहां के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के साथ उर्जा संसाधनों की आपूर्ति में मदद का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही वह दोनों देशों की मुद्राओं के आसान आदान-प्रदान के लिए भी पहल कर रहा है। यह उसकी युआन कूटनीति का परिचायक है। शेख हसीना के 'विजन 2041' की शुरुआत करीब डेढ़ दशक पहले हुई, चीन इसमें प्रमुख भागीदार बनाया गया और इसके विभिन्न चरण निर्धारित किए गए। 2009 में, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश की अवधारणा पेश की, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और शासन में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना था। यह विजन 2041 तक बांग्लादेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने और अग्रणी बनने के क्षमता निर्माण पर आधारित है।

इस विजन का मकसद आर्थिक विकास को गति देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटलीकरण पर जोर देना है। बांग्लादेश को डिजिटिल बनाने की दिशा में चीनी फोन निर्माता कंपनी ख्वावे लगातार काम कर रही है। अमेरिका ने कहा है कि 5जी उपकरणों के जरिए चीन ख्वावे का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इसमें कंपनी के मालिक रेन के संबंध पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से रहे हैं। वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 4100 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। इसकी सीमा भारतीय राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ लगी है।

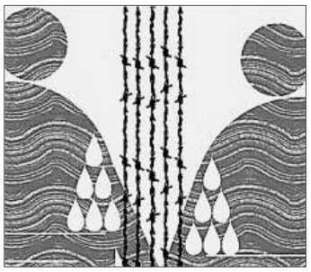

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से शेष भारत से जुड़ा हुआ है, सिक्किम और भूटान के रास्ते चीन से निकटता के कारण यह गलियारा भारत के लिए रणनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील है। इस संकीर्ण रास्ते से नेपाल, बांग्लादेश और भूटान भी जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी के जरिए पूर्वोत्तर के जुड़ाव की वजह से हमारी बांग्लादेश पर रणनीतिक निर्भरता काफी बढ़ गई है। डोकलाम में चीनी सक्रियता की वजह से भी बांग्लादेश पर हमारी निर्भरता काफी बढ़ जाती है। यह इलाका भूटान के नजदीक है। इससे हमारे लिए बांग्लादेश की भूमिका और बढ़ जाती है।

> हाल ही में शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हरित साझेदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति तो बनी है, लेकिन बांग्लादेश के चीन के साथ भी ऐसे ही समझौते भारत को आशंकित करते हैं। आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में चीनी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चिटगांव क्षेत्र में एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना समेत ऊर्जा आपूर्ति और नदी परियोजनाओं में चीन की दिलचस्पी से साफ है कि चीन बांग्लादेश के विकसित राष्ट्र बनने के सपने का प्रमुख भागीदार बन गया है।

भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए ख्वावे का सीमाई इलाकों में प्रभावशील रहना चिंताजनक है। अमेरिका अपने यहां ख्वावे के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा चुका है और चाहता है कि उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियों को भी 5जी नेटवर्क से हटाया जाए। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। चीन के 2017 के 'राष्ट्रीय जासूसी कानून' के अनुसार किसी भी संगठन को राष्ट्र के खुफिया काम में समर्थन और सहयोग देना आवश्यक है। इसका मतलब है कि चीन ख्वावे को किसी काम के लिए आदेश दे सकता है। इसलिए इसे लेकर अमेरिका और भारत की आशंका निर्मूल नहीं है।

चीन रक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों के बीच सहयोग सैन्य हार्डवेयर, समुद्री गश्ती जहाज, कोरवेट, टैंक, लड़ाकू जेट के साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली और जहाज रोधी मिसाइलों तक बढ़ गया है। भारत की हिंद प्रशांत रणनीति की दृष्टि से बांग्लादेश बेहद महत्त्वपूर्ण है। वहीं पूर्वोत्तर में अलगाववादी विद्रोहियों पर दबाव बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के सहयोग की भारत को सदा जरूरत होगी। बांग्लादेश के नौसैनिक मामलों में चीन की भागीदारी बढ़ रही है। इस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है।

हाल ही में शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हरित साझेदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति तो बनी है, लेकिन बांग्लादेश के चीन के साथ भी ऐसे ही समझौते भारत को आशंकित करते हैं। आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में चीनी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चिटगांव क्षेत्र में एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना समेत ऊर्जा आपूर्ति और नदी परियोजनाओं में चीन की दिलचस्पी से साफ है कि चीन बांग्लादेश के विकसित राष्ट्र बनने के सपने का प्रमुख भागीदार बन गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर चले आ रहे विवाद का समाधान नहीं हुआ है, अब चीन ने तीस्ता परियोजना को पूरा करने की इच्छा जताई है। तीस्ता परियोजना में चीन की भूमिका उसे भारतीय सीमा के बहुत करीब ले आएगी और उसका दायरा सिलीगुड़ी गलियारे के करीब तक होगा।

प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस 'विजन 2041' पर काम कर रही हैं, उसमें उनकी कूटनीति चीन की तरफ झुकी नजर आती है। इस योजना के चार मुख्य आधार तय किए गए हैं- सुशासन, लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण और क्षमता निर्माण। चीन की कर्ज नीति के चलते दुनिया के कई देशों में सुशासन और लोकतांत्रिक सरकारों को गहरी चोट पहुंची है। बेहद गरीबी से उबार कर शेख हसीना का अपने देश को विकसित देश बनाने का सपना तो अच्छा है, लेकिन उसमें चीन की व्यापक भागीदारी बांग्लादेश के भविष्य के लिए दुविधापूर्ण है ही, भारत की एकता और अखंडता के लिए भी समस्या बढ़ सकती है।

अहं की दीवारें

प्रदीप उपाध्याय

आजकल जिधर देखें, वहां 'मैं' का बोलबाला दिखता है। यह भाषा का नहीं, व्यक्ति का 'मैं' है। इस 'मैं' में ही सब कुछ है, दूसरा तुच्छ, दोयम दर्जे का हो जाता है। इसमें अहंकार परिलक्षित होता है, दंभ दिखाई देता है, स्वयं के श्रेष्ठ होने का मिथ्या अभिमान आभासित होता है! जबकि प्रत्येक मनुष्य में गुण-अवगुण का सम्मिश्रण होता है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जिसमें अपने गुणों को जानने-समझने का माद्दा होगा, वह अपने अवगुणों से स्वयं ही विरत हो जाएगा। जब कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, तब स्वयं की श्रेष्ठता का कैसा मिथ्याभिमान! पद-हैसियत, संपन्नता किसी मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं बनाते। अगर कोई अपने पद, अपनी हैसियत, आर्थिक संपन्नता के आधार पर श्रेष्ठता का घमंड करता है, तो यह उचित नहीं है। श्रेष्ठीजन अपनी बुद्धि के साथ विवेक से संचालित होते हैं, जिसके कारण उनमें अहंकार का भाव जागृत हो ही नहीं सकता। विवेकशून्य व्यक्ति ही अहंकार के वशीभूत होकर अपने सामने दूसरों को निकृष्ट मान बैठता है, जबकि व्यक्ति अपने गुणों और अपने अच्छे स्वभाव तथा व्यवहार के कारण ही सम्मान का अधिकारी होता है।

अपनी श्रेष्ठता का बखान करने वाले अहंकारी ही होते हैं। किसी व्यक्ति, समूह, वर्ग, विचार या फिर पंथ की श्रेष्ठता तभी मान्य हो सकती है, जब अन्य को यह महसूस हो, उनकी स्वीकृति प्राप्त हो और उन्हीं के द्वारा यह बात कही जाए। दबाव, हिंसा या अनैतिक आधार पर उच्चता साबित नहीं हो सकती है। यह अहंकार की अभिव्यक्ति ही होगी। अहंकारी मन किसी भी तरह के सत्य को सुनने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अहंकार के साथ झूठ है, फरेब है। किसी ने कहा भी है कि 'अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश, न मानो तो देख लो, कौरव, रावण और कंस'।

कहा गया है कि अहंकार राजा रावण का भी नहीं रहा। त्याग, सहनशीलता, विनम्रता के गुणों के कारण राजा राम पूजे जाते हैं, लेकिन आज के दौर में जहां किसी को कोई पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हुई नहीं कि उसमें अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में वह अपने से नीचे वाली स्थिति के व्यक्तियों की तौहीन करने लगता है, अपमानित करने लगता है। जबकि व्यक्ति के बड़ा होने पर उससे बड़प्पन की दरकार रहती है, न कि उसके अहंकारी हो जाने की।

निस्संदेह जब व्यक्ति में अहंकार कूट-कूट कर समा जाता है, तब उसकी सोचने-समझने की क्षमता का भी ह्रास हो जाता है। यानी अहंकारी व्यक्ति अच्छे-बुरे में भेद करने की क्षमता खो देता है। उसे लगता है कि जो वह कह रहा है या जो वह कर रहा है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या।

अहंकारी व्यक्ति सदैव श्रेष्ठता के मद में रहता है, दूसरे उसे तुच्छ और हीन ही दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि जो भी है, वह स्वयं है। उस पर 'मैं' का मिथ्या भाव हावी होने लगता है। जहां मैं है, वहां अहंकार है, दुख है, पीड़ा और पराभव है। अहंकारी मन अंतर्मन से उद्वेलित रहता है, समुद्र की लहरों की तरह अशांत। जो भी सामने आ जाए, उसे बहा ले जाने को उद्धत या फिर अपने में समा लेने की चाहत। अपने प्रति विरोध का स्वर कुचल देने की धृष्टता। जबकि इसके विपरीत जहां 'हम' का भाव समाहित हो जाता है, वहां सहयोग है, सद्भाव है। सुख है, मन झील के ठहरे हुए जल-सा शांत और निर्मल भाव में रहता है। कहीं कोई उद्वेग नहीं, कहीं कोई ईर्ष्या-द्वेष नहीं, सभी के प्रति समभाव, सद्भाव। दूसरों के अस्तित्व का सम्मान, उनके विचारों के प्रति कोई राग-द्वेष नहीं। सह-अस्तित्व की आकांक्षा यहीं आकर बलवती होती है।

अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को स्वीकार करने वाला कभी अहंकार नहीं करता। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक और एक ग्यारह होते हैं। उस एक को भी मान्यता समवेत होकर ही मिल सकती है। एक अकेला कभी भारी नहीं हो सकता। सेनापति भी अपनी सेना के बल पर ही आगे बढ़ सकता है और लड़ सकता है। सेनापति की विजय में भी सेना का ही बल होता है। विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर ने भी अपने विश्व विजय के अभियान में सेना का ही साथ लिया था। यानी सहयोग और सदाचार से ही जीवन रथ आगे बढ़ सकता है। फिर अहंकार किस बात का!

यहां एक उद्धरण जोड़ना भी प्रासंगिक होगा, जिसके अनुसार सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि जब उसका जनाजा निकाला जाए, तब उसकी दोनों हथेली बाहर की ओर लटकाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या व्यक्ति को अहंकारी, अभिमानी, घमंडी होना चाहिए? नहीं। जीवन बहुत छोटा है, बहुत सुंदर है। मिलजुल कर, सामंजस्य के साथ रहना सीखना चाहिए। त्याग, सहनशीलता, सहानुभूति, दया, ममता, वात्सल्य के गुणों से लबरेज रहकर लोगों के दिलों को जीतें, न कि घमंड, अहंकार में चूर रहकर अपनों से भी दूर हो जाएं। जीवन तभी संवरेगा और खुशहाल होगा, जब हम अपना अहंकार छोड़कर 'मैं' के स्थान पर 'हम' की भावना से संचालित होकर कर्म करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है- 'बूंद-सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां न बादशाह चलता है, न इक्का चलता है। ये खेल है अपने अपने कर्मों का/ यहां सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है।'

दुनिया मेरे आगे

> अहंकारी व्यक्ति सदैव श्रेष्ठता के मद में रहता है, दूसरे उसे तुच्छ और हीन ही दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि जो भी है, वह स्वयं है। उस पर 'मैं' का मिथ्या भाव हावी होने लगता है। जहां मैं है, वहां अहंकार है, दुख है, पीड़ा और पराभव है। अहंकारी मन अंतर्मन से उद्वेलित रहता है, समुद्र की लहरों की तरह अशांत।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

दिखावे के समारोह

पिछले कुछ वर्षों से वैवाहिक कार्यक्रम भव्यता की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। हाल ही में आई जेफरीज की एक रपट के मुताबिक, भारत में हर विवाह पर औसत खर्च 12.5 लाख रुपए है। भारतीय लोग शिक्षा से ज्यादा वैवाहिक कार्यक्रमों पर खर्च करते हैं। हकीकत यह है कि अब शादियां भव्य होती जा रही हैं और रिश्ते खोखले। शादी में किए जाने वाले खर्च को व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखा जाने लगा है और लोग शादियों में पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। शाही शादियों के पीछे एक बड़ा कारण उपभोक्तावाद की बढ़ती प्रवृत्ति और दहेज की लालसा है। जिस तरह से शादियों में दहेज का लालच बढ़ रहा है, उससे यह सवाल उठेगा कि क्या विवाह अपने स्वार्थ के लिए किया गया एक समझौता है। इसके अलावा, अब शादियों को दिखावे और प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जाने लगा है। परंपराओं के मुकाबले सब कुछ पूरी तरह बाजारवाद से प्रभावित है। सवाल है कि हमें इससे क्या प्राप्त हुआ, तो जवाब है बेतहाशा भोजन की बर्बादी, बढ़ती दहेज संस्कृति, लोगों पर बढ़ता कर्ज, बेटियों के जन्म को समस्या के रूप में देखा जाना। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

– सौरभ बुंदेला, भोपाल, मप्र

प्रकृति प्रथम

कुछ दिनों पहले तक उत्तर भारत के मैदानी इलाके भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे थे। लू सैकड़ों जिंदगियां लील गई। अब बारिश कहर बन कर आई। बाढ़, बिजली गिरने, इमारतों के ढहने, जलभराव आदि से लोग मरने लगे। असल में मौसम का यह रौद्र रूप मानव निर्मित है। इसके लिए बढ़ती आबादी, अंधाधुंध विकास, संसाधनों के अत्यधिक दोहन वाली उपभोक्तावादी संस्कृति, मानव का खुद को धरती का मालिक और सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझने जैसे कारक शामिल हैं। मौसम से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें पुनः इस्तेमाल करने की व्यवस्था को भी अपनाना होगा। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली हर आदत को अपने जीवन से निकालना होगा। प्रकृति प्रथम और मानव अंतिम की सोच अपनानी होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते समय प्राथमिकता प्रकृति को दी जाए और विकास एक सह उत्पाद की तरह हो।

– बृजेश माथुर, गाजियाबाद

बढ़ती खाई

प्रतिभाएं हर व्यक्ति में जन्म से ही निहित होती हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। बचपन से ही वह व्यक्ति अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ललक लिए रहता है। हालांकि ऐसी प्रतिभाएं तब धरी की धरी रह जाती हैं जब उसे अपनी प्रतिभाओं के दोहन के लिए संसाधनों के केंद्रीकरण का सामना करना पड़ता है। आक्सफेम के एक सर्वे के अनुसार मात्र एक फीसद लोगों के पास चालीस फीसद संसाधन और पचास फीसद लोगों के पास केवल तीन फीसद संसाधन हैं। सवाल है कि इस तरह के बंटवारे में कैसा समाज और कैसा देश बनेगा! तमाम वंचित लोग अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए मूलभूत संसाधनों- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित रह जाता है और इस गरीबी के दुश्चक्र में फंसता चला जाता है। आखिर उसकी प्रतिभा मर जाती है। इससे समाज में असमानता की गहराई ज्यादा बढ़ती जाती है और संसाधन कुछ एक लोगों तक ही केंद्रित होकर रह जाते हैं।

– दिलीप चौरसिया, बहराइच, उप्र

बिहार की बिसात

सन 2005 से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केंद्र में रही भाजपा और कांग्रेस सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिहार की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, जबकि जनता दल (एकी) ने विशेष दर्जे या विशेष पैकेज की बात कही है। इस मांग के समर्थन में राजग में शामिल लोक जनशक्ति और हिंदुस्तान अवाम पार्टी ने भी सुर में सुर मिलाया है, लेकिन इस मांग का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि यह मांग इतनी आसानी से केंद्र सरकार पूरी करने वाली नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग कुछ हद तक राजनीतिक दबाव की परिभाषा में भी आती है। हालांकि देश में कुल मिलाकर ग्यारह ऐसे राज्य हैं, जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 23 जुलाई 2024

बजट से आशा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024 संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण की रोशनी में देखा जाए तो यह बात ज्यादा स्पष्ट होकर उभरती है कि मंगलवार को पेश किए जाने वाले बजट से किस तरह की और कितनी उम्मीदें रखना व्यावहारिक होगा।

रोजगार है अहम | आर्थिक सर्वे में इस तथ्य को अच्छी तरह रेखांकित किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार सृजन की चुनौती कितनी अहम है। वर्कफोर्स में कृषि क्षेत्र का हिस्सा आने वाले वर्षों में कम ही होते जाना है। 2023 के 45.8% से घटते हुए 2047 तक यह 25% पर आने का अनुमान है। ऐसे में अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य हासिल करना है तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना होगा। आर्थिक सर्वे में हिसाब लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2030 तक सालाना 78.5 लाख रोजगार पैदा करने होंगे।

लगातार 7वां बजट आज

सामाजिक सुरक्षा | ध्यान रहे, पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और गिग इकॉनमी में ही रोजगार बढ़े हैं। इनमें कृषि क्षेत्र तो छिपी हुई बेरोजगारी के लिए जाना जाता है। फिर यहां हालात तेजी से पलट रहे हैं। निर्माण क्षेत्र में रोजगार अनियमित होते हैं तो गिग इकॉनमी के कामों में असुरक्षा रहती है। अगर देश में गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन करना है और वर्कफोर्स को सुरक्षा तथा निश्चितता देनी है तो PLI (प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव), मित्रा टेक्सटाइल और मुद्रा जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अलावा उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो न सिर्फ ज्यादा रोजगार दें बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।

महंगाई पर काबू | महंगाई एक और बड़ी चुनौती है जिससे निपटना जरूरी है। देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.1% के स्तर पर है तो खाद्य महंगाई दर 9.5% पर। हालांकि महंगाई की चुनौती लगातार बने रहने के पीछे महामारी और युद्ध से उपजे हालात के अलावा पिछले दो वर्षों के प्रतिकूल मौसम का भी हाथ रहा है, लेकिन इसे अनदेखा करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। सरकार और रिजर्व बैंक को इसके लिए तात्कालिक और दूरगामी दोनों ही स्तरों पर कदम उठाने होंगे।

शिक्षा और स्वास्थ्य | चुनौतियां कई स्तरों पर हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने का लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों को प्राथमिकता से लेना अनिवार्य बनाता है। यह उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि समाज के अलग-अलग तबकों को राहत देने की मजबूरियों के बीच भी बजट में इन दोनों क्षेत्रों को अधिकाधिक लोगों की पहुंच में लाने और इनकी क्वॉलिटी बढ़ाने के खास प्रयास दिखेंगे।

धूप-छांव

पीछे छूटते पहाड़

प्रणव प्रियदर्शी

जिसे हम अपने कठिन समय के रूप में जानते, भोगते और याद रखते हैं, वह प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने विश्वास को बनाए रखने की कोशिशों के अलावा भी कुछ होता है क्या?

सवाल मुझसे किसने, कब पूछा था, याद नहीं है, लेकिन यह मेरे अंदर है लंबे समय से। जब भी जिंदगी में पहाड़ जैसी समस्याएं आती प्रतीत होती हैं, पहले उन सबको मिलाकर एक पहाड़ का रूप देना, उसके बाद उस विशाल पहाड़ को चट्टानों के रूप में देखना, फिर उन चट्टानों को धूल-मिट्टी के कणों के रूप में महसूस करना और आखिर में अपने पैरों के नीचे मौजूद धूल कणों के बराबर का साबित करते हुए कदम-दर-कदम उसे पार कर जाना – यह संभव इसलिए होता है कि ऊपर बताया गया सवाल मेरे मन में मौजूद रहता है। यही उस समस्या के हर पहलू को जांचता-परखता है कि जो परिस्थिति बनी दिख रही है, जो पात्र मेरी ओर चुनौतियां फेंक रहे हैं, वे सब मुझे कठिन क्यों लग रहे, इसलिए क्योंकि वे मेरे अब तक के विश्वास के खिलाफ हैं। लेकिन जो मेरा मूल्यबोध है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसे लेकर जो बुनियादी समझ है मेरी, वह जब तक सिरे से गलत साबित नहीं हो जाती, तब तक कम से कम मुझे तो अपने इन विश्वासों के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए।

इस बिंदु तक पहुंचने के बाद लकीरें साफ हो जाती हैं। परिस्थितियां मुझे किस आचरण के लिए मजबूर करना चाहती हैं और मुझे कैसा आचरण करना चाहिए, इन दोनों के बीच स्पष्ट सीमा दिखने लग जाती है। फिर शुरू होता है वह संघर्ष जिसे आप कोई भी आकर्षक नाम दे सकते हैं, पर है वह रहस्य-रोमांच से भरपूर ऐसा थ्रिलर जिसमें अगले पल क्या होना है, दो कदम बाद ही कैसा मोड़ आने वाला है, नहीं पता होता। अपने मन का करने का संकल्प और उसका नतीजा देखने की जिज्ञासा- इन्हीं दोनों के बीच कब वे समस्याओं के पहाड़ पीछे छूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब अपने आसपास के लोगों की तालियां सुनाई देने लगती हैं। अचानक जैसे तंद्रा भंग होती है कि समस्याओं के जिन पहाड़ों से मैं घिरा था, वे तो कहीं हैं नहीं। मैं तो अपने प्रशंसकों के बीच हूं जो मेरी हिम्मत, धैर्य और सूझबूझ वगैरह की तारीफ कर रहे हैं। झुककर तारीफें ग्रहण करते हुए भी जैसे खुद को अहसास नहीं होता कि वे सच हैं। क्योंकि खुद तो उस रहस्य रोमांच से भरे थ्रिलर से गुजरते हुए ऐसा कुछ सोचने-समझने, महसूस करने का वक्त ही नहीं मिला होता है।

डिस्क्लेमर : ऊपर दिया गया पूरा ब्योरा मनगढ़ंत है। इसके झूठ-सच का फैसला अपने रिस्क पर, खुद आजमाकर ही करें।

बोल वचन

खिसियानी बिल्ली

राहुल पाण्डेय

खैनी पर ताल ठोंकते हुए पुट्टन चाचा मुझे सुना रहे थे- सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। रहा नहीं गया तो मैंने पूछ लिया, चाची ही बतावें, पुट्टन इतना खिसियान सा क्यों है। यह सुनते ही चाची खिल्ल से हंस पड़ीं और पुट्टन चाचा खिसिया गए। एक विज्ञापन की पंचलाइन थी- डर सबको लगता है। हर कोई खिसियाता है- यह भी उतना ही सच है। दफ्तर में बॉस की डांट पड़ने पर कर्मचारी खिसियाता है। खिसियाना तब भी पड़ता है, जब आप लाल बत्ती क्रॉस करते हुए पकड़े जाएं। तब भी, जब भंडारे की लाइन में दूसरी बार आने पर पकड़े जाएं। सुख-दुख की तरह खिसियाहट भी जीवन का एक अभिन्न अंग है, और हमारी देह का भी। खिसियाना यानी बेइज्जत होने के बाद का चिड़चिड़ापन। ऐसा नहीं कि जो किसी की बेइज्जती करते हैं, वे खुद नहीं बेइज्जत होते। किसी की बेइज्जती करने के बाद इंसान सबसे पहले आईने के सामने बेइज्जत होता है, बशर्ते वह इंसान ही हो। कुछ इसे हंसने से जोड़ते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर इंसान खिसियाकर दांत ही दिखाए। कुछ बेइज्जती चुपचाप पी जाते हैं तो कुछ जूता भी उतार लेते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान किसी इंसान से ही खिसियाए। वह मौसम से भी खिसियाता है। बारिश न होने से खिसियाए हुए इंसान मेढकों और कुत्तों तक की शादी कराने लग जाते हैं। इस खिसियाने के लिए इंग्लिश में frustration शब्द मिलता है। यह खिसियाने के कुछ पास तो पहुंचता है, लेकिन बीच में रास्ता खिसियानी बिल्ली काट जाती है।

Subrata Dhar

जो बाइडन के राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हटने के बाद चार गवर्नरों ने जताया चुनाव लड़ने का इरादा

क्या हवा का रुख़ बदल देंगी कमला हैरिस

ललित मोहन बंसल

'नामांकन लूंगी और चुनाव भी जीतूंगी', कमला हैरिस जोश में हैं। भारतीय मूल की अश्वेत कमला हैरिस को मालूम है कि जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने के बाद नामांकन हासिल करना सहज नहीं है। कई और प्रत्याशी इस दौड़ में शामिल हैं।

रिझाने की कोशिश | पिछले रविवार की दोपहर पता चला कि बाइडन चुनाव से हट रहे हैं। इसके बाद डेमोक्रेटिक राजनीति में जैसे पंख लग गए। कैलिफोर्निया और इलिनॉय सहित चार बड़े डेमोक्रेट राज्यों के गवर्नर राष्ट्रपति पद के नामांकन की दौड़ में शामिल हो गए। ऐसे भी कुछ सीनियर डेमोक्रेट हैं, जो मिनी प्राइमरी कर नामांकन मामले को उलझाने में लगे हैं। लेकिन चार साल उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद कमला यह बखूबी जानती हैं कि वह जिस पद पर हैं, उस वजह से उन्हें प्राथमिकता तो मिल सकती है, मगर सीधे नामांकन नहीं मिल सकता।

नैशनल कन्वेंशन पर निगाहें | डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन 19 अगस्त को है। इसके लिए सारी व्यवस्था हो चुकी है। चुनाव में अब 105 दिन ही बचे हैं। इसलिए कमला हैरिस ने देशवासियों, खासकर डेमोक्रेट सदस्यों से दो-टूक अपील की, 'आइए, हम सभी एकजुट होकर लड़ें, मिलजुल कर चुनाव जीतें।' इस अपील का असर भी हुआ। डेमोक्रेट बहुल कैलिफोर्निया के गवर्नर गेवन न्यूसम ने उनके समर्थन की घोषणा कर दी। रविवार शाम तक कमला हैरिस के समर्थन में एक दर्जन डेमोक्रेट बहुल राज्य और आ गए। न्यू यॉर्क स्टेट की महिला गवर्नर कैथी होचुल ने जोरदार अपील में कहा, 'कमला न्याय की प्रतिमूर्ति हैं। वह महिलाओं के लिए दिन-प्रतिदिन संघर्ष करने को तत्पर रहती हैं।'

कमला हैरिस में क्या है खास
- दूसरे डेमोक्रेट दावेदारों से आगे हैं
- अफ्रीकी-अमेरिकी वोटर हैं साथ
- मिल जाएगा बाइडन का चुनावी फंड

ओबामा का समर्थन नहीं | कमला कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इमिग्रेशन और गर्भपात जैसे बड़े मुद्दों पर बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं। इसके विपरीत डॉनल्ड ट्रंप चार आपराधिक मामलों में कसूरवार और 91 अदालती मामलों अभियुक्त रह चुके हैं। हालांकि ट्रंप को सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन एक बड़ा वर्ग आज भी उनके वैयक्तिक चाल-चलन से नाखुश है। जिन चार राज्यों के गवर्नर चुनावी राजनीति में आगे आना चाहते हैं, वे सभी लोकप्रियता में कमला हैरिस से बहुत पीछे हैं। इसके बावजूद शीर्षस्थ डेमोक्रेट बराक ओबामा सहित सीनेट और प्रतिनिधि सभा के नेता कमला का समर्थन नहीं कर पाए।

मजबूत वोट बैंक | कमला हैरिस के पक्ष में एशियाई अमेरिकी के साथ बड़ी संख्या में अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी एकजुट होकर खड़े हैं। अफ्रीकी अमेरिकी 19 प्रतिशत हैं। इनके अलावा लैटिन अमेरिकी मूल के बारह से पंद्रह प्रतिशत मतदाता रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी पर भारी पड़ते हैं। बराक ओबामा को पहले टर्म में अश्वेत, भारतीय और लैटिन अमेरिकी समुदाय से 84 प्रतिशत मत मिले थे। कहा जा रहा है कि भारत के तमिल, तेलुगू और मलयाली सहित अन्यान्य प्रवासी भारतीय कमला के पक्ष में एकजुट होते जा रहे हैं। इस अश्वेत, अफ्रीकी अमेरिकी, भारतीय अमेरिकी समुदाय की देश के छोटे-बड़े छह स्विंग स्टेट में इतनी पैठ है कि वह चुनाव के रुख को बदल सकता है। कहा जा रहा है कि कट्टर ईसाई समुदाय में इवेंजिलिस्ट के अहंकारी स्वभाव के कारण कमला हैरिस का वोट बैंक स्थिर है। उसका रिपब्लिकन खाते में जाना संभव नहीं है।

AI Image

चुनावी फंड का फायदा | कमला हैरिस के पक्ष में डेमोक्रेट वोट बैंक के साथ एक बात और जा रही है। उन्हें जो बाइडन के चुनावी फंड में जमा करीब सात सौ करोड़ रुपये मिल सकेंगे। यही नहीं, बाइडन के नाम वापस लेने भर से उसके बाद के पांच घंटों में छोटे-छोटे दानदाताओं ने दो सौ सत्तर करोड़ रुपये उनकी झोली में डाल दिए हैं। ऐसे ही बड़े डोनर्स की ओर से भी समर्थन मिल रहा है। एक ताज़ा एशियन अमेरिकन वोटर सर्वे में कहा गया है कि यह समूह तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पिछले चार वर्षों में पंद्रह प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस समुदाय के सामने मुख्य मुद्दे रोज़गार, हेल्थ/मेडिकेयर, महंगाई और मकानों के बढ़ते किराये हैं।

ट्रंप की पॉलिसी से नुकसान | भारत और अमेरिका के बीच सामरिक और व्यापार संबंधी नीतियों का भारतीय अमेरिकी मतदाताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। लोग यह भी भूले नहीं हैं कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन से बढ़ते आयात और घटते निर्यात की पृष्ठभूमि में दस से बीस प्रतिशत सीमा शुल्क लगा कर चीनी कंपनियों को निरुत्साहित किया था। इससे दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों में दरार आ गई थी। अमेरिकी हितों के संरक्षण में अगर चीन और भारत के विरुद्ध व्यापारिक और सामरिक नीतियों में बदलाव लाए जाते हैं तो निश्चित रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय अमेरिकी समुदाय पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

आउटसोर्सिंग रोकने का इरादा | डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों भारत और चीन में आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कहकर भारत में आईटी और हेल्थकेयर में फार्मा कंपनियों को रुष्ट कर लामबंद किया है। इसका डेमोक्रेट प्रत्याशी को लाभ होना निश्चित है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और लॉस एंजिलिस में रहते हैं)

माइक्रोसॉफ्ट को 'माइक्रोहार्ड' होना मांगताए

दीपक पाचपोर

अपुन का फ्रेंड बाबूराव बोले तो एकदम झक्कास आईटम। उसकूं कोई बी बात का कबी बी टेंशन नईं होताए। जबी पूछताए कि 'भिड़ू, तुम अईसा टेंशन फ्री कईसा रहताए', तबी वो अपुन कूं मस्त टिप्स देताए। उसका पास गल्ली का नाली सफाई से लेके परमाणु हत्यार तक अक्खा प्रॉब्लेम का सोल्यूशन मिलेंगा। उसका सोल्यूशन थोड़ा आड़ा-तिरछा रहताए इस करके खाली सुन के लेने का। वापरने का नईं।

अबी एक दिन अपुन बाबूराव को पूछेला, 'बॉस ये पॉलिटिक्स का भीतर बोले तो टपोरी लोग भौत आएला। उसका क्या करने का? गौरमेंट काएकूं कुछ नईं करताए?' बाबूराव मस्त स्माइल देके क्या कहताए वो जरा सुन के लेने का। पैले वो पूछताए कि 'भिड़ू, तुमकूं कोई का तकलीप होएंगा तो बताने का। अपुन इदर से खाली एक फोन घुमाएंगा उदर तुमारा घर पे पुलिस आके पूछ के जाएंगा कि कोई बी प्रॉब्लेम होताए वो बताने का।' जबी अपुन कहेला कि अपुन कूं कोई प्रॉब्लेम नईं होताए। अपुन तुमारा माफिक टोटल बिंदास रहताए, तबी बाबूराव बोलताए, 'बस, बिंदास रहने का! पन तुम जो पूछेला उसका थोड़ा सुन के लेने का! अबी टपोरीगिरी अऊर पॉलिटिक्स दोनों टोटल मिक्सअप हुएला। तुम समज नईं सकताए कि मवाली लोग कूं गौरमेंट बनाताए कि मवाली लोग सरकार बनाताए।' जबी अपुन पूछेंगा कि तबी क्या करने का, वो कहेंगा कि गौरमेंट बनाने का ज़रूरत नईं। अपुन पूछा कि 'जबी गौरमेंट नईं रहेंगा तबी काम कईसा चलेंगा?' बाबूराव कहेंगा, 'अबी तुमकूं लगताए क्या कि गौरमेंट होताए? हाफिसर लोग काम नईं करताए, गटार का सफाई नईं होताए, रोड पे अक्खा लोग सिग्नल तोड़ताए।' अपुन बोला, 'तुम इसका कम्प्लेन्ट करने कूं सकताए गौरमेंट का पास। इस करके गौरमेंट होना मांगताए।' बाबूराव- 'पन तुमारा पसंत का गौरमेंट कबी बनताए क्या? नईं न? अपुन फुल टू कन्फ्यूज़ होके पूछेला- 'फिर क्या करने का बाबूराव?' वो कहताए- 'कुछ नईं करने का। वोटिंग नईं करने का, खल्लास!' अपुन अंगार बनके बोला- 'बाबूराव, तुम डेमोक्रेसी में अईसा बात करताए, टोटल रॉन्ग।' बाबूराव बोला, 'अबी अपुन तुमकूं कहताए कि जईसा तुम इत्ता बरस तुमारा नापसंती का सरकार का भीतर लाइफ निकाला ना, वईसाइच कोई बी प्रॉब्लेम कूं लेके जास्ती भंकस नईं करने का। शांति से रैने का।' अपुन बाबूराव का बात याद करके थोड़ा ठैरा। पैले दोनों चा पियेला। फिर अपुन पूछेला- 'बाबूराव, तुमकूं पता पड़ा क्या उदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वाट लगेला। कित्ता फ्लाइट कैंसिल हुएला, बैंक का सर्वर डाउन हुएला?' बाबूराव बोलताए, 'बॉस, अपुन इदर बईठेलाए पन अक्खा बातमी इदर चलके आताए। अक्खा दिन मचमच हुएला पन अपुन टोटल मजा लेताए।' अपुन बोला- 'अक्खा दुनिया में बोमाबोम हुएला अऊर तुम मजा लेताए?' बाबूराव- 'जबी अपुन कूं किदर बी फ्लाइट पकड़के जाने का नईं तबी काएकूं टेंशन लेने का। बैंक का सर्वर डाउन होताए तबी बी कोई टेंशन नईं। पईसा आज नईं तो कल आएंगा। तुमकूं हजार-पांच सौ मांगताए तबी अपुन कूं बोलने का।' अपुन कहेला- 'अपुन कूं नईं मांगताए पन तुमारा पास अईसा प्रॉब्लेम का सोल्यूशन होताए क्या?' बाबूराव फुल टू कॉन्फिडेंस का साथ बोलताए- 'तुमारा दोनों प्रॉब्लेम का बोले तो एकईच सोल्यूशन होताए। 'माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़' का बदले थोड़ा 'माइक्रोहार्ड विंडोज़' वापरने का। तुम जित्ता सॉफ्टली काम करेंगा न बॉस, तुमारा उत्ताइच वाट लगेंगा। अबी अपुन का लोकशाही विंडोज़ से काम करताए, वो बी सॉफ्ट वेरायटी का। एक तो उसकूं गेट से आना मांगताए भाऊ, अऊर वो बी थोड़ा हार्ड होके। उसकूं कोई तोड़ने कूं नईं सकताए। तबी वो बी काम करेंगा अऊर गौरमेंट बी काम करने कूं सकताए।

AI Image

खाली पीली

शेयर करें अपने अनुभव
आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं nbtreader@timesgroup.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें-'खाली पीली'

विशेष मांग से कब तक बचेगी सरकार

नरेन्द्र नाथ

विशुद्ध राजनीति कसौटी

लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आया। इसके साथ ही किसी राज्य को स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस देने का मामला भी देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। इसकी वजह हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। इस बार मोदी सरकार को चलने के लिए नायडू की TDP और नीतीश के JDU के सहारे की जरूरत है। ये दोनों ही नेता अपने-अपने राज्य को स्पेशल स्टेटस और पैकेज दिलाने की मांग उठाते रहे हैं। ऐसे में जब दोनों नेता केंद्र सरकार में मजबूत भागीदार बने, तो उन पर इस मुद्दे को उसी अनुरूप उठाने का दबाव बढ़ा। अब यह दबाव कहां तक बनाया जाता है, आने वाले समय में केंद्र सरकार की स्थिरता बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर रहेगी।

अभी सरकार का इनकार है

JDU ने संसद के मौजूदा सत्र में ही बिहार को स्पेशल स्टेटस का मामला उठाने की मांग कर दी थी। सर्वदलीय बैठक में भी पार्टी की ओर से यह मुद्दा उठाया गया। हालांकि सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने जा रहा है। सरकार ने इसकी वजह भी बताई है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से पहले कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। उन राज्यों की कुछ विशेषताएं थीं, मसलन - पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगना वगैरह। देश में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ये राज्य हैं - अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, नगालैंड, सिक्किम, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। स्पेशल स्टेटस देने के पीछे गाडगिल फॉर्म्युले को पैमाना बनाया जाता है। ऐसा दर्जा मिलने पर केंद्र से मिलने वाली रकम में से 90% ग्रांट के रूप में मिलती है और बाकी का 10% कर्ज। दूसरी ओर सामान्य राज्यों को केंद्र से दी जाने वाली रकम का महज 30% ही अनुदान होता है।

आसान नहीं पीछे हटना

सरकार ने भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार, अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज की मांग से पीछे हटने का सियासी विकल्प इन दोनों में से किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि बजट से पहले नायडू ने दो बार दिल्ली की यात्रा की। यह दौरा बस मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी संबंधित लोगों से मुलाकात की। साथ ही, आंध्र के लिए स्पेशल पैकेज की मांग सार्वजनिक मंच से रखी। ऐसी भी खबरें आईं कि केंद्र सरकार चंद्रबाबू की मांग के अनुरूप आंध्र प्रदेश में कई निवेश और प्रॉजेक्ट शुरू करने को तैयार है। हालांकि चंद्रबाबू अपनी सारी मांगों के अलावा कुछ भी कम स्वीकारने को राजी नहीं। दरअसल, 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर ही TDP ने मोदी सरकार का साथ छोड़ा था। बाद में पार्टी ने इसे BJP के खिलाफ बड़ा मुद्दा भी बनाया था। अब उन पर उनके ही प्रदेश में अपने इस स्टैंड पर टिके रहने का स्वाभाविक दबाव है। यही स्थिति JDU की है। उस पर राज्य के भीतर इस मांग को पूरा कराने के लिए बहुत दबाव है। RJD इस मामले पर नीतीश कुमार को लगातार घेर रही है। सरकार के स्पेशल स्टेटस देने से इनकार करने के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने हमला और तेज कर दिया। यह मुद्दा आगे भी बना रहने वाला है।

असीमित मांग, सीमित विकल्प

स्पेशल स्टेटस के साथ दोनों राज्यों ने स्पेशल पैकेज की भी मांग रखी थी। अब यहां केंद्र सरकार और BJP के सामने दोहरी चुनौती है। केवल इन दो राज्यों की मांग को पूरा करना केंद्र के लिए आसान नहीं है। लेकिन, इनकी मांगों को पूरी तरह अनदेखा करने का जोखिम भी सरकार और पार्टी नहीं ले सकती। इन दोनों राज्यों की मांग को देखते हुए बाकी सूबे भी अपनी विशलिस्ट लेकर आ गए हैं। वहीं, साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो सरकार इन सूबों की नाराजगी भी नहीं मोल लेना चाहेगी। जानकारों के अनुसार स्पेशल पैकेज का पिटारा एक बार खुल गया तो इससे निकलना केंद्र के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में सरकार नई मुसीबत को आमंत्रित करने से पहले सौ बार उसका आकलन करेगी। आर्थिक स्तर पर भी सरकार के सामने उतनी स्वतंत्रता नहीं है कि राज्यों को राजनीतिक कारणों से बड़ा-बड़ा पैकेज दे सके। वित्तीय घाटे के कारण कई राज्य केंद्र सरकार के सामने आर्थिक मदद के लिए पहले ही कतार में लग चुके हैं।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ महिलाओं के हक़ में

22 जुलाई का लेख 'सुप्रीम फैसले से याद आया शाह बानो केस' पढ़ा। 1980 के दशक में शाह बानो केस ने भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक बहस छेड़ दी थी। इंदौर के वकील मोहम्मद अहमद खान ने अपनी तलाकशुदा पत्नी शाह बानो को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। उनका तर्क था कि वह सिर्फ इस्लामी शरीयत कानून के अनुसार जिम्मेदार हैं, न कि भारतीय दंड संहिता (CRPC) की धारा 125 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 1984 को यह तर्क खारिज कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में एक और फैसला सुनाया, जो लैंगिक समानता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

माम चंद सागर, ईमेल से

■ मजबूत हों रिश्ते

'खाली पीली' कॉलम में 9 जुलाई को पब्लिश लेख 'लीकेज से घबराना नईं, ऑटोमेटिक रुकेंगा', की भाषा हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक है। इसमें भारतीय संस्कृति और समाज को उभारने की कोशिश की गई है। यह लेख हमारे समाज में आम बातों को लेकर फैली जिज्ञासा और अत्यधिक प्रतिक्रियाओं पर व्यंग्य करता है। लेखक ने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और एयरपोर्ट की स्थितियों का उपयोग करके इस प्रवृत्ति को दर्शाया है।

विजय पाटिल, ईमेल से

■ जन भावनाओं का सम्मान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी। इसका उद्देश्य हिंदू समुदाय को एकजुट कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, आदिवासी शिक्षा को बढ़ाना, स्व-रोजगार और धर्मांतरण से रक्षा करना था। अब सरकार ने संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। यह फैसला स्वागत योग्य है। सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान किया है।

मीना धानिया, सिरसपुर

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

कोचिंग हब से बाहर के छात्र भी बने टॉपर - एक खबर
- क्या इससे पैरेंट्स और स्टूडेंट्स का भ्रम टूट पाएगा!

धीरेंद्र पाठक

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

शिव और प्रकृति को समझने का अवसर है सावन

मयंक मुरारी

हम अपने चारों ओर जितनी भी चीजें देखते हैं, उसका एक आकार होता है, लेकिन हमारी चेतना निराकार है। एक मूर्ति भी निर्गुण होती है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो भक्त के हृदय में उस मूर्ति की धड़कन सुनाई देने लगती है। यानी मूर्ति के साथ हमारी निष्ठा एक जीवंत रूप ले लेती है। भक्त उस मूर्ति के माध्यम से असीम और अनंत से जुड़ जाता है। शिवलिंग की पूजा में यही खासियत है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय चेतना और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह निराकार ब्रह्म का साकार रूप है, जिसमें समस्त सृष्टि समाहित है। शिवलिंग का आकार याद दिलाता है कि आत्मा का स्वरूप भी उसी शिवलिंग के समान है।

धार्मिक दृष्टि से शिवलिंग की पूजा परम तत्व से सीधा संबंध स्थापित करने का माध्यम है। भक्तजन शिवलिंग को शिव के सगुण रूप में देखते हैं, जिसमें अनंत शक्ति और दिव्यता निहित है। इसके माध्यम से वे शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सावन का महीना अनुकूल माना जाता है। सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पिया था, जिससे उन्होंने देवताओं और दानवों, दोनों को बचाया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसी कारण से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। सावन के महीने में वातावरण शुद्ध और ताजगी से भरा होता है। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से न केवल धार्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह पर्यावरण की शुद्धि में भी सहायक होता है। बेलपत्र का महत्व भी विशेष रूप से है, क्योंकि यह शिव को अत्यंत प्रिय है और इसका औषधीय महत्व भी है।

शिवलिंग भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह न केवल धार्मिक स्थलों पर स्थापित होता है, बल्कि कला, साहित्य और संगीत में भी इसकी व्यापकता है। शिवलिंग की पूजा और प्रतिष्ठा समाज के विभिन्न आयामों को एक साथ जोड़ती है। शिवलिंग के गोलाकार और अंडाकार रूप को पृथ्वी और ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों के संतुलन के रूप में देखा जाता है। योग और तंत्र परंपराओं में शिवलिंग को ऊर्जा केंद्र (चक्र) और चेतना के उच्चतम स्तर का प्रतीक माना जाता है। इन सभी दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट होता है कि शिवलिंग केवल एक धार्मिक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अर्थों से जुड़ी हुई है। यह प्रतीक हमें सिखाता है कि निराकार ब्रह्म को साकार रूप में कैसे अनुभव किया जा सकता है और इस अनुभव से जीवन की गहराइयों को कैसे समझा जा सकता है।

अस्तित्व अनंत आकाश में समाया है। यह अंतरिक्ष असीम है और इसमें तारे, सूर्य और निहारिका के रूप में आकार हैं। वह ब्रह्म स्वयं निर्गुण है, लेकिन उसकी रचनाएं सगुण और साकार हैं। भारतीय दर्शन की एक विशेषता है कि यहां जो देखा गया, सुना गया, वही गाया गया। अग्नि, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, रुद्र, विष्णु, वरुण की शक्तियां आदि काल में मनुष्यों को सम्मोहित करती थीं। बाद में ऋषियों ने इन सारे देवों को वृक्षों में देखा, जहां हरियाली, फूल और सुगंध दिखे।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75 निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक स्थापना वर्ष : 1948

वई दिल्ली ■ मंगलवार, 23 जुलाई 2024

हिंसा अयोग्य लोगों का अंतिम हथियार है।
-इसाक एसिमोव

जब पूरी दुनिया 3.2 फीसदी की दर से विकास कर रही है, तब आर्थिक सर्वे के मुताबिक, भारत में 2024-25 में विकास दर साढ़े छह से सात फीसदी हो सकती है, जो इसका संकेत है कि अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अलबत्ता देखना होगा कि महंगाई और रोजगार की चुनौतियां इसमें बाधक न बनें।

मजबूती की ओर

वित्तमंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक, अगले वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर साढ़े छह से सात फीसदी रह सकती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सात फीसदी के अनुमान के बराबर और विश्व बैंक के 6.6 फीसदी के अनुमान से ज्यादा ही है, जो यह दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ कदम बढ़ा रही है। हालांकि पिछले वर्ष के सर्वेक्षण में साढ़े छह फीसदी की विकास दर का अनुमान व्यक्त किया गया था, जिसके उम्मीद से कहीं ज्यादा 8.2 फीसदी रहने का अनुमान है। सर्वेक्षण का यह कहना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर बनी हुई है और तमाम भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद लचीलेपन का प्रदर्शन कर रही है। दरअसल, 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था पर चुरा असर डाला था, लेकिन सर्वे बताता है कि अपनी सुदृढ़ राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में महामारी के प्रभाव से तेजी से मुक्त होकर पहले की स्थिति में तो आई ही है, इसने कोविड के बाद अपनी स्थिति को और भी मजबूत किया है। सर्वेक्षण यह भी बताता है कि कोरोना महामारी के बाद देश की वार्षिक बेरोजगारी दर में गिरावट आई है और युवा (15 से 29 वर्ष) बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8 फीसदी से गिरकर 2022-23 में दस फीसदी पर आ गई है, जो रोजगार की आशाजनक तस्वीर दिखाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार पैदा करने की संरचनात्मक क्षमता पर उठ रहे सवालों पर भी विराम लगाती है। हालांकि, बढ़ते श्रम बल को देखते हुए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में देश में हर साल तकरीबन 78.5 लाख नौकरियां पैदा किए जाने की जरूरत को सर्वे में स्वीकारा गया है, जो एक बड़ी चुनौती है। बढ़ती महंगाई को काबू में रखने की चुनौती भी है, जिस पर आर्थिक सर्वेक्षण का यह कहना आश्वस्त करता है कि केंद्र सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप और केंद्रीय बैंक के मूल्य स्थिरता उपायों की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4 फीसदी पर बनाए रखा जा सका है, जो महामारी के बाद का निम्नतम स्तर है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी अगले वित्त वर्ष तक वित्तीय घाटे को कम करके जीडीपी के साढ़े चार फीसदी या इससे भी नीचे लाने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी आमदनी बढ़ाने के दूसरे उपायों को तलाशना होगा। आश्वस्त करने वाली बात है कि जब पूरी दुनिया 3.2 फीसदी की औसत विकास दर से बढ़ रही है, तब वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत सर्वे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर पेश करते हुए दर्शाता है कि देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।

क्या हैरिस लड़ेंगी हारी हुई लड़ाई?

कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की सबसे अलोकप्रिय उपराष्ट्रपतियों में से एक हैं। पिछले साल उनकी लोकप्रियता 41 फीसदी थी, जो 38 फीसदी रह गई है। ऐसे में ट्रंप को चुनौती देना उनके लिए आसान नहीं होगा।

मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप से बहस में पिछड़ने के बाद तीन हफ्ते से बढ़ रहे लगातार दबाव के चलते आखिरकार जो बाइडन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा के कुछ ही मिनट बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में अपना समर्थन देने का एलान कर दिया। वहीं, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष जैमे हैरिसन ने वादा किया है कि बाइडन का उत्तराधिकारी चुनने के लिए पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए डेमोक्रेटिक मिलकर कमला हैरिस को राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में अपना समर्थन देंगे।

उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं कमला हैरिस के लिए ट्रंप को चुनौती देना आसान नहीं होगा। 2020 के चुनाव में कमला हैरिस का प्रदर्शन प्रभावी रहा था, लेकिन अब स्थितियां पहले जैसी नहीं हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में प्रशासन संभालने के बाद बाइडन ने कमला हैरिस को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थीं, जिनमें से एक आप्रवासन का मुद्दा था। यह ऐसा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए आज भी प्रमुख चुनावी कमजोरी है। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ आव्रजन प्रवाह के 'मूल कारणों' को संबोधित करने के उनके अप्रभावी प्रयासों के लिए उनकी व्यापक रूप से आलोचना की गई है।

जैरेड मॉन्ड्सचीन
सिडनी विश्वविद्यालय में अमेरिकी अध्ययन केंद्र के शोध निदेशक

इसके अलावा, बाइडन की लोकप्रियता में आई कमी के साथ ही कमला की ख्याति भी घटी है। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास की सबसे अलोकप्रिय उपराष्ट्रपतियों में से एक हैं। जुलाई 2023 में जहां उनकी लोकप्रियता 41 फीसदी थी, वह जून-जुलाई 2024 में गिरकर 38 फीसदी पर आ गई। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने के लिए डेमोक्रेटिक के टिकट पर कमला हैरिस राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी लोकप्रियता प्रभावी ढंग से बढ़ी है, बल्कि वह इसलिए डेमोक्रेट उम्मीदवार बन सकती हैं, क्योंकि बाइडन कमजोर पड़ गए थे।

खुद के कमजोर पड़ने पर बाइडन ने कमला हैरिस का राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में किया समर्थन।

हैरिस के सामने अभी कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं। पहले भी उपराष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना आसान माना जाता रहा है, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। पिछले डेढ़ सदी के इतिहास को देखें, तो 17 उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा है। उनमें बाइडन, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, रिचर्ड निक्सन समेत पांच उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में सफल रहे। हैरिस जल्द ही अपना रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित करेंगी, जो कोई पुरुष हो सकता है, ताकि वह मतदाताओं को आश्वस्त कर सकें कि वह बाइडन की तुलना में ज्यादा प्रगतिशील हैं। अगर वह आधिकारिक रूप से डेमोक्रेट उम्मीदवार घोषित हो जाती हैं, तो संदेहशील रुढ़िवादी मतदाताओं को आश्वस्त करने के लिए वह शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में अपने वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख करेंगी।

दूसरी तरफ रिपब्लिकन प्रत्याशी ट्रंप नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने अपना रनिंग मेट भी चुन लिया है। बाइडन के साथ मीडिया बहस में बहुत कम ही बढ़त बना पाने के बाद वह काफी आगे दिख रहे हैं और आत्मविश्वास से लबरेज हैं। बाइडन द्वारा कमला हैरिस को समर्थन दिए जाने को भी डोनाल्ड ट्रंप अपने एजेंडे में शामिल कर सकते हैं। अब ट्रंप को सीधी टक्कर देने के लिए कमला हैरिस के पास अपने चुनाव अभियान के लिए समय भी काफी कम बचा है। उन्हें इतने ही कम समय में काफी कुछ करना होगा।

- द कन्वर्सेशन से

बांग्लादेश : संकट और संदेश

जब भी बांग्लादेश में कोई आंदोलन होता है, तो बीएनपी, जमात-ए इस्लामी एवं अन्य कट्टरपंथी समूह उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना को चरम भ्रष्टाचार और विकराल बेरोजगारी पर काबू पाना होगा, ताकि इनकी आड़ में कट्टरपंथी ताकतें अपने मंसूबों में कामयाब न हो सकें।

बांग्लादेश एक बार फिर संकट के कगार से वापस लौट आया है, जिसमें न्यायालय के उस निर्णय से मदद मिली है, जिसमें 1971 में पाकिस्तान के साथ मुक्ति युद्ध में संघर्ष करने वाले लोगों के वंशजों के लिए शैक्षणिक संस्थानों एवं नौकरियों में आरक्षण कोटे में भारी कटौती की गई है। अदालत ने स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे को 30 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया है, जबकि नस्लीय अल्पसंख्यकों के दो फीसदी के कोटे को बरकरार रखा है और योग्यता आधारित चयन के लिए 93 फीसदी सीटें खुली रखी हैं।

शीर्ष अदालत ने आरक्षण को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि निचली अदालत के उस फैसले को रद्द किया है, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। शीर्ष अदालत के इस फैसले ने शेख हसीना सरकार और आंदोलनकारी छात्रों, दोनों की प्रतिष्ठा बचाई है। लेकिन काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हसीना सरकार, जो विरोध प्रदर्शन की गंभीरता का आकलन करने में पूरी तरह विफल रही, बाद के हालात से कैसे निपटती है। यह एक लंबी प्रक्रिया की केवल शुरुआत है, जबकि सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार और युवाओं में बेरोजगारी जैसे गहरे कारण अब भी बने हुए हैं।

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

हसीना के इस बयान ने भी आंदोलन को हवा दी कि 'अगर स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं, तो क्या रजाकारों के लिए आरक्षण होना चाहिए।' उनका यह बयान इस्लामवादियों के खिलाफ उनके राजनीतिक हमले का एक हिस्सा था, जो अंदर और बाहर से उन्हें चुनौती देते रहते हैं। 'रजाकार' उन समूहों को कहा जाता है, जिनका इस्लामाल पाकिस्तानी अधिकारियों ने 1971 में बांग्लादेश के हितों के खिलाफ किया था। इससे आंदोलनकारियों को भड़का दिया, जो किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबद्धता से इन्कार करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के आंदोलन का एक लंबा इतिहास है, जिन्हें कथित रूप से सत्ता का संरक्षण हासिल है, जो किसी भी विरोध प्रदर्शन को हथिया लेते हैं और मौजूदा प्रदर्शन इसका अपवाद नहीं है।

आंदोलनकारी छात्र आरक्षण की इस व्यवस्था को भेदभावपूर्ण मानते हैं और योग्यता के आधार पर भर्ती की मांग करते हैं। आजादी के बाद से यह बांग्लादेश का सबसे खराब संकट है, जिसमें अनुमानतः 100 से 130 लोगों की मौतें हुई हैं (आलोचकों का दावा है कि वास्तविक संख्या इससे अधिक है)। आंदोलन कई हफ्तों तक चला। इस आंदोलन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जमात-ए इस्लामी एवं अन्य सामाजिक रूप से शक्तिशाली इस्लामी कट्टरपंथी समूहों की भूमिका देखी जा सकती है।

पंद्रह साल से अधिक समय से लगातार सत्ता में काबिज हसीना, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला नेता हैं, जो वस्तुतः एकतरफा शासन करती हैं और उन पर तानाशाही के आरोप हैं। उन्हें बढ़ते मध्यम वर्ग से भी निपटना है, जो उनकी सरकार की आर्थिक प्रगति से मजबूत हुआ है, जो महत्वाकांक्षी है और नौकरी व बेहतर जीवन चाहता है। मुक्ति आंदोलन बांग्लादेशियों की भावनात्मक जीवन रेखा है, लेकिन आबादी के एक बड़े वर्ग ने उसमें भाग नहीं लिया था। इसी वर्ग की तीसरी पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी तीसरी-चौथी पीढ़ियों को मिलने वाले आरक्षण को गैर-जरूरी मानती है, और अपनी कीमत पर कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए जाने से नाराज है।

17 करोड़ की आबादी वाले इस दक्षिण एशियाई राष्ट्र में आंदोलन कोई नई बात नहीं है, पिछले हफ्ते के प्रदर्शन जितने तीव्र थे, वैसे आज तक नहीं देखे गए। हालांकि 2009 में शेख हसीना के सत्ता में लौटने के बाद से बांग्लादेश तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन अन्य विकासशील देशों की तरह इसने पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं की है। यह कोविड-19 महामारी के कारण मंदी से जूझ रहा था, जब यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। एक अनुमान के मुताबिक, 1.8 करोड़ बांग्लादेशी युवा रोजगार की तलाश में हैं।

कम पढ़े-लिखे की तुलना में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है। यह संकट मुल्क में सामाजिक बदलाव की स्थिति को भी दर्शाता है। पिछले आंदोलनों का नेतृत्व सरकारी विश्वविद्यालयों ने किया था, लेकिन इस बार निजी विश्वविद्यालयों की भागीदारी भी बराबर रही, जहां धनी परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। इस संकट ने बांग्लादेश के पड़ोसी देशों को भी चिंतित किया। वास्तव में यह आंदोलन तभी पनपने लगा था, जब हाल ही में हसीना ने दो बार भारत का दौरा किया। हसीना सरकार के प्रति दोस्ताना रवैया रखने वाले भारत ने इसे बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बताया है, जबकि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के पूर्वोत्तर राज्यों ने नेपाली, भूटानी एवं अन्य राष्ट्रों के छात्रों को वहां से निकलने में मदद की। 4,300 किलोमीटर की सीमा के दोनों ओर 600 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे व्यापार और मानव आवाजाही प्रभावित हो रही है।

विधायिका एवं कार्यपालिका पर काफी पकड़ रखते हुए भी हसीना मदद के लिए न्यायपालिका पर निर्भर थीं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार है, जिसके कारण देश ही नहीं, विदेश में भी उनकी आलोचना होती है। आलोचकों का कहना है कि बांग्लादेश के जन्म के साथ ही जिस तरह से शासन चलाया जाता रहा है, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसका फायदा सत्ता केंद्र के आसपास के लोग तो उठाते ही हैं, प्रशासन एवं बढ़ते व्यवसायी वर्ग भी उठाते हैं।

पिछले हफ्ते हसीना ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और यह बहुत पुरानी समस्या है। उन्होंने अपने एक घरेलू सहायक (चपरासी) के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि उसने कथित तौर पर 3.4 करोड़ डॉलर जमा कर लिए थे। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि इतनी धनराशि केवल सरकारी ठेकों के लिए पैरवी, भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी से ही जमा की गई होगी। सत्ता में उनका लंबे समय तक बने रहना आकांक्षाओं और गुस्से, दोनों को जन्म देता है। यह संकट हसीना के लिए चेतावनी है कि अगर वह देश को मध्यम आय वाला राष्ट्र बनाना, इसे बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथियों से सुरक्षित रखना और अपने पिता व बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को पूरा करना चाहती हैं, तो उन्हें कई मुद्दों से निपटना होगा।

edit@amarujala.com

दूसरा पहलू

कोको किसान जितने गरीब होते जाते हैं, विश्व बाजार में कोको और चॉकलेट की कीमतें उतनी ही बढ़ती जाती हैं।

चॉकलेट की मिठास नहीं है कोको किसानों के जीवन में

बत्तीस वर्षीय इमैनुएल फ्रिम्पोंग घाना में कोको उत्पादक किसान हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त की है। नौकरी नहीं मिली, तो वह पुश्तैनी खेत पर काम करने लगे। उन्होंने बताया, 'मैं यह काम करने को तैयार हूं।' उनकी साक्षरता और अंग्रेजी ज्ञान उन्हें अपने साथी किसानों और सरकार के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम करने में मदद करते हैं।

अमेरिका एवं अन्य देशों में कोको बीन्स एवं चॉकलेट उत्पादों के लिए जो अधिकतम मूल्य दिए जाते हैं, वे फ्रिम्पोंग एवं अन्य किसानों के जीवन को मुश्किल से प्रभावित कर पाते हैं। वह कहते हैं, जीवन की स्थितियां और पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। कोको बीन्स के लिए सरकार जो भुगतान करती है, वह कम है और किसानों को मिलने वाला सरकारी समर्थन अपर्याप्त है। मसलन, सी परिवार एक ही कॉटनाशक स्प्रेयर साझा करते हैं। कोको किसानों की गरीबी को कभी-कभी चॉकलेट खरीदारों एवं विक्रेताओं की विफलता के रूप में देखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह बाजार की विफलता है। एक स्वस्थ बाजार में कीमतों में उछाल अपने आप ठीक हो जाता है-जब कीमतें बढ़ती हैं, उसका लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कोको उत्पादक देश आयवरी कोस्ट एवं दूसरे नंबर के उत्पादक घाना के किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। ज्यादातर किसान गरीबी में जीते हैं। उनके पास नए कोको पेड़ लगाने, उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई और मजदूरी देने के लिए धन नहीं है।

पीटर कॉय
कोको बीन्स के लिए सरकार जो भुगतान करती है, वह कम है और किसानों को मिलने वाला सरकारी समर्थन अपर्याप्त है। सी परिवार एक ही कॉटनाशक स्प्रेयर साझा करते हैं।

एक तरफ, न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो में लोग चॉकलेट के लिए भारी कीमतें चुका रहे हैं, दूसरी तरफ बीन्स उगाने वाले लोग इससे अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं। जाहिर है, कुछ तो गड़बड़ है।

कुछ किसान घटती पैदावार की भरपाई के लिए ज्यादा जमीन पर खेती कर रहे हैं, जिसके चलते जंगल कट रहे हैं। कुछ किसान कोको की खेती छोड़ मक्का या रबर की खेती करते हैं, तो कुछ अपनी जमीन अवैध सोने के खनन के लिए बेच रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए विनाशकारी है। कोको किसान जितने गरीब होते जाते हैं, विश्व बाजार में कोको और चॉकलेट की कीमतें उतनी ही बढ़ती जाती हैं, क्योंकि कम पूंजी वाले किसान कम बीन्स का उत्पादन करते हैं या पूरी तरह से छोड़ देते हैं। यह विनाशकारी है, या अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के शब्दों में 'कम आय का जाल' है। सरकार द्वारा संचालित प्रणाली किसानों को तब लाभ पहुंचाती है, जब विश्व में कीमतें कम होती हैं, लेकिन जब कीमतें अधिक होती हैं, तो यह बोझ बन जाती है। एक तरफ न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो में लोग चॉकलेट के लिए भारी कीमतें चुका रहे हैं, दूसरी तरफ बीन्स उगाने वाले लोग इससे अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं। जाहिर है, कुछ तो गड़बड़ है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

खरीफ फसलें

इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई 15 जुलाई तक पिछले साल से 53.75 लाख हेक्टेयर अधिक हुई। फसलवार ज्यादा बुआई के आंकड़े-

तिलहन	25.35
धान	19.86
दलहन	12.82
कपास	2.77
गन्ना	0.82

आंकड़े पिछले साल की तुलना में ज्यादा बुआई के लाख हेक्टेयर में हैं। चोत : PIB

प्रचेता भाइयों के तप से प्रसन्न भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि तुम्हें ब्रह्मा के समान पुत्र होगा और तुम्हारा स्मरण करने वालों को भी अपने भाइयों से प्रेम होगा।

भाइयों में प्रेम बढ़ाता है 'प्रचेता' स्मरण

महाराज पृथु के वंश में बर्हिषद नाम के राजा हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर समुद्र की शतद्रुति नामक कन्या से विवाह किया। बर्हिषद और शतद्रुति के प्रचेता नाम के दस पुत्र हुए। प्रचेतागणों के युवा होने पर उनके पिता ने उन्हें विवाह कर संतानोत्पत्ति के लिए कहा। सभी भाइयों में बड़ा ही प्रेम था।

उन्होंने उत्तम संतान की उत्पत्ति के लिए भगवान की भक्ति करने का निश्चय किया। सभी भाई तप करने के लिए समुद्र की ओर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक सरोवर से निकलते हुए भगवान शंकर ने दर्शन दिए। शंकर जी ने उन्हें अद्भुत श्लोकों का एक स्तोत्र बताया और कहा कि हे राजपुत्रो! तुम इसका पाठ कर भगवान विष्णु की तपस्या करो। मुझे भगवान और उनके भक्त, दोनों ही बहुत प्रिय हैं। प्रचेता भाइयों ने जल में खड़े होकर दस हजार वर्ष तक भगवान की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और वरदान दिया कि तुम्हें ब्रह्मा के समान एक लोक प्रसिद्ध पुत्र होगा। साथ ही कहा कि जो भी संध्या के समय तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका भाइयों से प्रेम होगा।

अंतर्यात्रा संकलित

प्रचेतागणों ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि प्रत्येक जन्म में संतों का संग मिले। इसके बाद वृक्षों की दी हुई मारिषा नामक कन्या से प्रचेतागणों ने विवाह किया। बताया जाता है कि मारिषा के गर्भ से ही ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने जन्म लिया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 जुलाई, 1956

प.एशिया व यूरोपीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्रियों में मतभेद

राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन दो दिन के लिए स्थगित हो गया। कल की बैठक में पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) और यूरोपीय सुरक्षा, दोनों ही विषयों पर प्रधानमंत्रियों के बीच मतभेद उभरकर सामने आए।

पाकिस्तान की समस्याओं का अंत नहीं

पाकिस्तान के गंभीर आर्थिक संकट से ही नहीं, बल्कि अपने मुल्क के दहशतगर्दों से भी सामना करना पड़ रहा है।

कुलदीप तलवार — **पड़ोस**

पाकिस्तान को जहां अपनी गंभीर आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है, वहीं उसे अपने देश के दहशतगर्दों का भी सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में बन्नू की फौजी छावनी में एक आत्मघाती हमले में आठ सुरक्षाकर्मी मारे गए। शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार का अस्तित्व भी खतरे में है। सरकार में आपसी मतभेद बढ़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं को सुलझाने के बजाय भारत में अशांति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जो बेहद निंदनीय है।

पाकिस्तान फिलहाल भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और नकदी की कमी के कारण उसे भुगतान संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पाकिस्तान को सात अरब डॉलर कर्ज के तौर पर देने पर विचार कर रहा है। लेकिन कर्ज को लेकर आईएमएफ की कुछ कठिन शर्तें भी हैं, जो पाकिस्तान को पूरी करनी होंगी।

जैसे कि पाकिस्तान को कर (टैक्स) आधार व्यापक बनाने के अलावा राजकोषीय और मौद्रिक नीति को मजबूत करने, राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों के प्रबंधन में सुधार, प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए निवेश खातिर सुरक्षित व्यवस्था करने आदि की शर्तों को पूरा करना होगा।

फिलहाल आईएमएफ ने पाकिस्तान को तीन साल का एक पैकेज आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए दिया है, जिससे उसे काफी हद तक आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिलेगी। यह मदद 2023 'स्टैंड बाय अरेंजमेंट' के तहत दी गई है। इस तरह की मदद आईएमएफ भुगतान संकट का सामना कर रहे अपने सदस्य देशों को देता है।

इधर पाकिस्तान ने अपने सालाना बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे उसे टैक्स से आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। काबिले गौर है कि पाकिस्तान अब चौदहवीं बार आईएमएफ के सामने कर्ज के लिए हाथ फैलाने जाएगा। पाकिस्तान में पहली बार 1958 में अयूब खान की फौजी सरकार आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गई थी और उसने कर्ज हासिल किया था। आईएमएफ के कहने पर अब गैस, बिजली और बुनियादी जरूरतों की चीजों के रेट तय किए जा रहे हैं।

आईएमएफ ने नए कर देने वालों की संख्या 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख करने के लिए कहा है। सेल टैक्स में भी बढ़ोतरी का प्रावधान है। खेतों के लिए बीज, खाद, ट्रैक्टर पर पूरा सेल टैक्स लगाने की बात की गई है। निस्संदेह नए टैक्स मुल्क में महंगाई में बढ़ोतरी करेंगे, इससे पाकिस्तान में रोष देखा जा रहा है। सरकार ने आयकर अदा करने वालों की श्रेणी कम करके चार कर दी है। इससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ की शर्तों पर अमल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

पाकिस्तान के बजट के बारे में न सिर्फ पाकिस्तानी आवाम, बल्कि वहां के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने भी यह आरोप लगाया है कि आईएमएफ से कर्ज लेकर आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम सरकार बनाना ही नहीं, गिराना भी जानते हैं। जाहिर है, राष्ट्रपति आईएमएफ से कर्ज लेने के हक में नजर नहीं आते। शरीफ सरकार के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने खुद स्वीकार किया है कि बजट में लगाए गए कर से लोग तनाव में हैं। उनके राजस्व प्रस्ताव की सबने आलोचना की थी।

हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जून में अपने कुछ मंत्रियों व सहयोगियों के साथ चीन गए थे। इस शिष्टमंडल में सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर भी शामिल थे। उनका मकसद चीन से माली मदद हासिल करना था। इससे पहले कि वे चीन से माली मदद मांगें, चीन ने पाकिस्तान से ताईवान, शिनजियांग, शिझांग, हांगकांग और दक्षिण सागर पर समर्थन की मांग की।

पाकिस्तान चाहता था कि चीन उसके मुल्क में नई परियोजना में 46 अरब डॉलर का निवेश करे, लेकिन चीन ने केवल 25 अरब डॉलर के निवेश की पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी। पुरानी योजनाओं में सबसे प्रमुख बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की परियोजना है। इनमें ज्यादातर चीन के ही इंजीनियर और मजदूर काम रहे हैं और स्थानीय लोग गवादर एरिया में बलूची मजदूरों पर बराबर जानलेवा हमले करते रहते हैं। इसलिए चीन पाकिस्तान से उनकी सुरक्षा करने का भरोसा चाहता है। शहबाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और आपसी रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प लिया।

पाकिस्तान के आर्थिक संकट का अंत होता नहीं दिखता। अब देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान में हालात क्या शक्ल अख्तियार करते हैं।